स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–24, अंक–6
ज्येष्ठ – आषाढ़ 2073, जून 2016

संपादक
विक्रम उपाध्याय

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-37

कवर तृतीय पेज 39
कवर चतुर्थ पेज 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

सरकारी निवेश ही अब विकल्प

डॉ. भरत झुनझुनवाला

1 कवर पेज
2 कवर द्वितीय पेज
08 **ज्वलंत मुद्दा**
राजन आधारित मुद्रानीति का औचित्य क्या? ..... विक्रम उपाध्याय
10 **कृषि**
राजन आधारित मुद्रानीति का औचित्य क्या? ..... देविंदर शर्मा
12 **कूटनीति**
चाबहार एवं भारत–ईरान सहयोगः एक चिर अपेक्षित रणनीतिक पहल ..... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा
15 **आपातकाल की याद**
जब ठेंगड़ी जी ने हिसंक संघर्ष को तर्कों से काटा ..... सरोज मित्र
17 **अर्थनीति**
बंद होता कर चोरी का मॉरिशस रास्ता ..... डॉ. अश्वनी महाजन
19 **वैकल्पिक ऊर्जा**
सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति संभव ..... सतीश कुमार
21 **जलवायु**
गरमाती धरती के खतरे ..... निरंकार सिंह
23 **आयुर्वेद**
आयुर्वेद में अस्थमा का उपचार ..... स्वदेशी संवाद
26 **रिपोर्ट**
राष्ट्रीय परिषद बैठक, भोपाल (म.प्र.) ..... स्वदेशी संवाद
33 **व्हाटसएप**
चीनी एक सफेद जहर
38 **रिपोर्ट**
पर्यावरण जागरूक रैली, जमशेदपुर (झारखंड) ..... स्वदेशी संवाद

पाठकनामा

मोदी जी को कोटिशः बधाई

प्रधानमंत्री मोदी देश में भले ही राजनैतिक दलों के बीच वो सम्मान एवं समर्थन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो एक विश्व नेता के रूप में उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अमरीका, जापान, कनाडा, मैक्सिको जैसे बड़े देशों के नेताओं ने मोदी को विश्व राजनीति का ध्रुव तारा मान लिया है। हम भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय है। वास्तव में देखा जाए तो मोदी जी ही अकेले नेता है जो निचले स्तर पर गांव में सिलेंडर पहुंचाने से लेकर देश को परमाणु निर्यात समूह यानि एन. एस.जी. की सदस्यता दिलाने तक के लिए समान रूप से मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं। उनको कोटि–कोटि बधाई।

उज्ज्वल, *दिल्ली*

❋❋❋❋❋

स्वदेशी पत्रिका का नया क्लेवर आकर्षक

स्वदेशी पत्रिका का अप्रैल 2016 अंक पढ़ा। वैसे तो मैं पहले भी स्वदेशी पत्रिका पढ़ता रहा हूं, परंतु पिछले कुछ अंकों से मैं महसूस कर रहा हूं कि स्वदेशी पत्रिका पहले के मुकाबले ज्यादा आकर्षित रूप में प्रकाशित हो रही है। अब स्वदेशी पत्रिका देखने में भी काफी अच्छी लगती है और उसमें प्रकाशित लेख एवं सामग्री, खासकर अप्रैल अंक से आयुर्वेद पर एक कालम एवं मई माह से व्हाटसएप कालम काफी ज्ञान एवं लाभप्रद है। आयुर्वेद का क्षेत्र काफी विस्तृत है। इस विषय को हम लगातार पत्रिका में प्रकाशित कर सकते हैं। जिससे पाठकों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी उपलब्ध हो और उसको अपने जीवन में अपना सके। आयुर्वेद पद्धति को अगर हम अपने जीवन में प्रयोग करे तो हम निरोगी एवं दीघार्यु रह सकते हैं। इस पत्रिका की सहायता से देश की आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक एवं जलवायु संबंधी जानकारियां नवीनतम रूप में उपलब्ध होती है। समय की आवश्यकता है कि स्वदेशी पत्रिका को अब रंगीन पृष्ठों के साथ प्रकाशित किया जाए।

प्रवीण दीक्षित, *बागपत, उत्तर प्रदेश*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

भारत अमरीका के बीच सहज और मधुर संबंध के लिए मोदी जी की कोशिश को हम मोदी सिद्धांत का नाम देते हैं।

बराक ओबामा
राष्ट्रपति, अमरीका

बैंकों का पैसा लेकर भागने वालों को चैन की नींद नहीं सोने देंगे।

अरूण जेटली
वित्तमंत्री, भारत

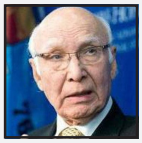

भारत अमरीका के बीच बढ़ती दोस्ती से हमें खतरा है।

सरताज अजीज
पाक विदेशी मंत्रालय सलाहकार

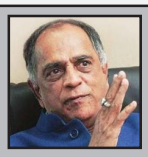

मोदी का चमचा कहलाने पर हमें गर्व है।

पहलाज निहलानी
सेंसर बोर्ड अध्यक्ष

ऐसा लगता है कि हम तानाशाह उत्तरी कोरिया में रह रहे हैं।

अनुराग कश्यप
फिल्म निर्माता

संपादकीय

सरकार के दो सालः बदलाव के आसार

विश्व के अधिकतर देश मंदी की चपेट में हैं और उनकी विकास दर नीचे आ रही है, परंतु हम अपने पड़ोसी चीन को पछाड़ते हुए सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वर्ष की आखिरी तिमाही में हमारी सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर यानी जीडीपी 7.9 फीसदी आंकी गई है। यह कोई तुक्का नहीं है, बल्कि सरकार की जी तोड़ मेहनत, सूझबूझ से बनाई गई नीतियां और सतत् प्रयास का नतीजा है। यूपीए की सरकार से विरासत में खराब अर्थव्यवस्था मिलने के बाद सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। एक तो पूर्ववर्ती सरकार के खराब काम, जिनमें नीतियों के मामले में पंगु, कुशासन और भ्रष्टाचार भी शामिल है, का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने से रोकना और दूसरे अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर वापस लाना। वर्ष 2014–15 में हमारी जीडीपी में 7.2 फीसदी थी और 2015–16 में 7.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। संसाधनों की कमी के बावजूद हम राजकोषीय घाटे को 2014–15 में 4.1 फीसदी और 2015–16 में 3.9 फीसदी तक रोकने में कामयाब रहें। 2016–17 में भी राजकोषीय घाटा 3.5 फीसदी तक सीमित रहने का अनुमान है। आपूर्ति में बेहतर संयोजन और राजकोषीय घाटे पर अंकुश के कारण मुद्रा स्फीति वृद्धि दर भी नियंत्रण में रही। वर्ष 2015 में भारत बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल रहा, जिसके कारण पूंजीगत खाते में भुगतान संतुलन हमारा सकारात्मक हो गया, 2015–16 में चालू खाते का भी भुगतान संतुलन आधिक्य रहा और रुपये पर से भी दबाव कम हो गया, जो कि लगातार डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा था और इसका भारी अवमूल्यन हो रहा था। वर्ष 2011–12 में जीडीपी वृद्धि दर कम होकर 6.5 फीसदी पर आ गई थी। इस वर्ष औद्योगिक विकास दर भारी रूप से गिरकर 2.9 फीसदी के निचले स्तर पर आ गई थी जो बाद में और नीचे जाकर नकारात्मक स्थिति में पहुंच गई। राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का लगभग 6 फीसदी तक पहुंच गया था। यूपीए शासन की गलत नीतियों के कारण लगभग 14 लाख करोड़ रुपये का कोष फंसा पड़ा था। दिसंबर 2012 में जारी रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट बताती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक काफी बुरी स्थिति में थे। चाहे वह टेलीकॉम क्षेत्र हो या कोयला या कोई अन्य क्षेत्र निर्णय प्रकिया में छद्म पूंजीपति जिन्हें क्रोनी कैपिटलिस्ट भी कहते हैं, हावी हो गए थे। यह एक तरह से पूर्ण नीतिगत पंगुता की स्थिति थी। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन ओईसीडी के अनुसार वर्ष 2015 की तरह आगे भी विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तीन फीसदी से भी कम रहने वाली है। अमरीका, चीन, ब्राजील समेत दुनिया के तमाम देश इस समय मंदी की जकड़ में है। केवल विकसित देश ही नहीं, बल्कि विकासशील देश भी विकास में गिरावट से जूझ रहे हैं। विकास की गति आगे करने और विकासशील देशों में आर्थिक विकास के विस्तार को तेज करने में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2015 के अंत में वैश्विक व्यापार वृद्धि दर मात्र 0.6 फीसदी थी। वास्तविक रूप में देखे तो वर्ष 2015 में जो विश्व व्यापार 19 खरब डॉलर का था वह संकुचित होकर 2015 में 16.5 खरब डॉलर रह गया। पिछले दो वर्षों में चीन का आर्थिक प्रदर्शन लगातार खराब रहा। पिछले 25 वर्षों में पहली बार चीन का जीडीपी वर्ष 2015 में गिरकर 6.9 फीसदी पर आ गया। वर्ष 2016 में चीन की विकास दर में और गिरावट आई और यह पहली तिमाही में 6.7 फीसदी दर्ज की गई। इसके ठीक विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार उचीं विकास दर हासिल कर रही है और दुनिया में सबसे तेज बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है। इस वर्ष अप्रैल में मुख्य क्षेत्रों की मजबूत विकास दर 8.5 फीसदी दर्ज की गई, जो कि पिछले वर्ष अप्रैल 2015 में नकारात्मक स्तर पर 0.2 फीसदी थी। यूपीए शासन के दौरान लंबित कई परियोजनाएं भी चालू कर दी गई हैं और उनका भी सुखद परिणाम 2015–16 में सामने आने लगा है।

सरकारी निवेश ही अब विकल्प

विश्व बैंक में वोटिंग के जादा अधिकार अमरीका तथा यूरोप के देशों के पास है। इन सरकारों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां चलाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित साधने के लिये जरूरी है कि विकासशील देशों की अपनी गति को स्थगित कर दिया जाये।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

सरकार का दावा है कि अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत से अधिक की सम्मानजनक गति से आगे बढ़ रही है। पर अभी तक जमीनी स्तर पर विकास नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र के एक सीमेंट विक्रेता ने बताया कि बिक्री 30 प्रतिशत कम है। दिल्ली के एक टैक्सी चालक ने कहा बुकिंग कम हो रही है। इसके विपरीत बड़ी कंपनियां ठीक–ठाक हैं। उनके कर्मचारी कहते हैं कि मांग दुरुस्त है। बहरहाल आम आदमी से जुड़ा धंधा कमजोर है। संभवतया इसका प्रमुख कारण मोदी सरकार की ईमानदारी है। हमारी अर्थव्यवस्था को काले धन की लत पड़ चुकी थी। मोदी सरकार इससे देश को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बड़ा गौरव है।

अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जो काले धन से चल रहे थे उनमें सुस्ती अभी भी है। इस दुष्प्रभाव को प्रॉपर्टी बाजार में स्पष्ट देखा जा सकता है। इस बाजार को राजनीतिक संरक्षण में दो तरह से चलाया जा रहा था। सरकारी जमीन को बिल्डर को सस्ते दाम पर आवंटित कर रिश्वत के रूप में मोटा धन लिया जाता था, इससे बिल्डर की बुक में लागत कम हो जाती थी। साथ–साथ भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के काले धन को भी परियोजना में लगाया जाता था। इससे बिल्डर के निवेश करने की क्षमता बढ़ जाती थी। मोदी सरकार ने यह काला धन बंद कर दिया है। बिल्डर को न तो सस्ती दिखने वाली जमीन मिल रही है और न ही भ्रष्ट नेताओं का काला धन ही इसमें आ रहा है। इसी प्रकार फैक्ट्री लगाने के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र भी घूस देकर आसानी से मिल जाता था। अब प्रदूषण नियंत्रण वाले संयंत्र लगाने पड़ रहे हैं, जिससे लागत बढ़ रही है और उद्यमी पीछे हट रहे हैं। देश में औद्योगिक गतिविधियां सीमित हो गई है। जो शायद विश्व बैंक और विदेशी कंपनियों के हितों को ज्यादा पोषित कर सकती है।

सरकार विश्व बैंक के बनाये जाल में फंसती चली जा रही है। विश्व बैंक पश्चिमी देशों

के इशारे पर काम करता है। विश्व बैंक में वोटिंग के ज्यादा अधिकार अमरीका तथा यूरोप के देशों के पास है। इन सरकारों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां चलाती हैं जैसे अमरीकी उद्योगपति डानल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित साधने के लिये जरूरी है कि विकासशील देशों की व्यवसायिक गति को धीमी कर दी जाये।

विश्व बैंक का प्रयास है कि भारत बीमार हो जाये और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शरण में जाये। इस उद्देश्य को साधने के लिये विश्व बैंक ने हिदायत दी है कि भारत द्वारा वित्तीय घाटे को न्यून रखा जाये। सरकार द्वारा ऋण लेकर हाइवे अथवा पावर प्लांट न बनाया जाये। गांवों में वाईफाई का प्रसार न हो तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग लगाने के लिये सरकार सब्सीडी न दे। ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ये काम किये जायेंगे और इसका लाभ कमाने का अवसर देश के उद्यमियों के स्थान पर उन्हें ही मिलेगा।

विश्व बैंक की नीति सफल हो सकती थी यदि दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में तेजी होती। विश्व अर्थव्यवस्था में चौतरफा मंदी व्याप्त है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्वयं संकट में हैं। ऐसे में वे भी निवेश से विमुख हैं। अतः विश्व बैंक की नीति असफल सिद्ध हो रही है।

मोदी सरकार की ईमानदारी के कारण काले धन पर नियंत्रण हुआ है। यह सरकार की उपलब्धि का सकारात्मक पहलू है। परिणाम यह हुआ है कि काले धन से चल रही अर्थव्यवस्था मंद पड़ी है। किंतु विश्व अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी निवेश से कतरा रही हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के तीनों इंजन यानि काला धन, सरकारी खर्च और विदेशी निवेश सुस्त पड़े हुये हैं।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये इन तीनों में से एक को ठीक से चलाना ही होगा। काले धन को छूट देना अनैतिक है और देश के दीर्घकालीन विकास में बाधक है। साथ ही भाजपा के ईमानदार शासन उपलब्ध कराने के वायदे के विपरीत है।

दूसरा माडल विदेशी निवेश का है। इस इंजन की चाल हमारे हाथ में नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तब ही भारत में निवेश करेंगी जब उनके देशों में माल की मांग हो। जैसे फिनलैंड में मोबाइल फोन की मांग हो तो नोकिया द्वारा भारत में मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्री लगाई जा सकती है। परिस्थिति यह है कि नोकिया अपने स्टाक में रखे माल को ही नहीं बेच पा रही है। ऐसे में वह भारत में कोई नई परियोजना नहीं लगायेगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अब तक सफल नहीं होने के कई कारणों में एक कारण यह भी है कि दुनिया भर में मांग सिमट चुकी है।

अर्थव्यवस्था के तीन इंजन में दो नाकाम हैं। काला धन अनैतिक है। सच्चा विदेशी निवेश पस्त है। ऐसे में एक मात्र इंजन सरकारी निवेश ही अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है।

हालांकि सरकार ने दावा किया है कि विदेशी निवेश में भारी मात्रा में वृद्धि हुयी है। ये आंकड़े तकनीकी दृष्टि से सही हो सकते हैं, परंतु वास्तविक नहीं हैं। आने वाले विदेशी निवेश में भारत से बाहर भेजी जाने वाली पूंजी का बड़ा हिस्सा घूमकर देश में फिर आने वाली पूंजी का ही हिस्सा है। अपना ही पैसा विदेश घूमकर वापस घर आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत से बाहर जाने वाली पूंजी में भारी वृद्धि हुयी है। भारतीय निवेशकों द्वारा अपनी पूंजी को विदेश भेजकर विदेशी निवेश के रूप में वापस लाया जा रहा है। यही कारण है कि विदेशी निवेश में कथित वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी हुयी है।

अर्थव्यवस्था के तीन इंजन में दो नाकाम हैं। काला धन अनैतिक है। सच्चा विदेशी निवेश पस्त है। ऐसे में एक मात्र इंजन सरकारी निवेश ही अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। सरकार ऋण लेकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकती है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायेगी। मान लीजिये कोई उद्यमी फैक्ट्री लगाना चाहता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईमानदार है। उसे प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाना ही होगा। इसमें अतिरिक्त खर्च आता है। इस खर्च को वहन न कर पाने के कारण वह फैक्ट्री लगाने में असमर्थ है। सरकार के सामने विकल्प है कि नई फैक्ट्री पर सब्सिडी दें ताकि उद्यमी के लिये फैक्ट्री लगाना लाभप्रद हो जाये। इससे अर्थव्यवस्था में गति आ जायेगी। परंतु विश्व बैंक ने ऐसा करने को मना कर रखा है। लेकिन सरकार के पास सार्वजनिक वित्त पोषण के जरिये अर्थव्यवस्था को गति देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मोदी सरकार ने इस मामले में बहुत सारी घोषणाएं की भी है। सत्ता में आने के बाद ही जिन परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा 2014–15 के बजट में की गई उनमें पांच औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाः दिल्ली–मुंबई, बंगलूरू–मुंबई, चैन्नई–बंगलूरू, विजाग–चैन्नई, अमृतसर–कोलकत्ता और 100 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं शामिल थी।

2016–17 में भी 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के जरिये ढांचागत एवं कृषि से जुड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार को चाहिये कि विश्व बैंक की इन बातों की अनसुनी करके देश में सच्चे सरकारी निवेश को बढ़ाये व मंदी को तोड़े। अन्यथा दो साल बीत चुके हैं, समय फिसलता जा रहा है। ❑❑

राजन आधारित मुद्रानीति का औचित्य क्या?

रघुराम राजन सितंबर 2016 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहें या ना रहें, लेकिन अपने तीन साल के कार्यकाल में उन्होंने राजनोमिक्स का दबदबा स्थापित करके दिखा दिया है। राजनीतिक आकाओं को खुश कर वाहवाही लूटने के बजाय राजन ने अपने फैसलों पर दृढ़ता और अपनी सोंच पर भरोसा रखने का फार्मूला अभी तक कायम रखा है। पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के सलाहकार से भारतीय केंद्रीय बैंक के प्रमुख बनने तक भले ही उन्होंने अपनी कोई छाप नहीं छोड़ी, लेकिन सितंबर 2013 को सुब्बाराव से आरबीआई की कमान लेने से लेकर आज तक बैंकिंग और मुद्रा बाजार में सिर्फ अपनी ही चलाते आ रहे हैं। भले ही उनके फैसलों को लेकर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आती रहीं, कुछ लोग उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने का श्रेय दे रहे हैं तो कुछ लोग कॉरपोरेट की हत्या और बाजार में मांग गायब करने वाले बता रहे हैं। भाजपा नेता सुब्रम्णयम स्वामी कहते हैं 'राजन ऐसा डॉक्टर है, जो बुखार का बेहतर इलाज मरीज को मार देना मानता है।'

कभी राजन को लेकर तल्ख टिप्पणी करने वाले चिंदबरम आज उनके सबसे बड़े समर्थक हैं। चिदंबरम ने कहा था कि यदि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने में उनके साथ नही आता तो वे अकेले चलने के लिए तैयार हैं। आज वहीं चिदंबरम यह कह रहे हैं कि राजन अर्थव्यवस्था को समझने वाले बेहतरीन दिमाग वाले शख्स हैं। पर वास्तव में राजन है क्या? एक दक्षिण भारतीय परिवार में जन्में, दिल्ली के स्कूल डीपीएस आरकेपुरम में स्कूली शिक्षा प्राप्त राजन आईआईटी दिल्ली से प्रौद्यगिकी में स्नातक के बाद आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री लेकर विदेश गये, फिर वहां पढ़ने पढ़ाने में कई साल लगाने के बाद आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए। भारत में पी चिदंबरम ने उन्हें अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया और फिर आरबीआई का चीफ। इस बीच उन्होंने अमरीका का ग्रीन कार्ड भी हासिल कर लिया। भाजपा में संघ पृष्ठभूमि के नेता और स्वदेशी विचार धारा वाले लोग अमरीकी ग्रीन कार्ड को भी उनका

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के सलाहकार से भारतीय केंद्रीय बैंक के प्रमुख बनने तक भले ही उन्होंने अपनी कोई छाप नहीं छोड़ी, लेकिन सितंबर 2013 को सुब्बाराव से आरबीआई की कमान लेने से लेकर आज तक बैंकिंग और मुद्रा बाजार में सिर्फ अपनी ही चलाते आ रहे हैं।

– विक्रम उपाध्याय

अमरीका परस्त होना बताते हैं। अकेले सुब्रमण्यम स्वामी ही राजन के आलोचक नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भी राजन को विदेशी सोंच वाला बता चुके हैं।

जब राजन ने आरबीआई की कमान संभाली थी, तो देश के सामने कई चुनौतियां थी। एक तो महंगाई तेजी से बढ़ रही थी और दूसरे रुपये में भारी गिरावट देखी जा रही थी। विकास दर भी घट कर पांच फीसदी के पास आ गया था। विदेशों में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर से डंवाडोल के रूप में देखा जाने लगा था। वैसे में राजन ने अपने नेतृत्वकौशल और अर्थव्यवस्था की बेहतरीन समझ का परिचय दिया। उनकी पहली कोशिश साढ़े तीन फीसदी तक व्यापार घाटे को लाना था, दूसरी कोशिश मुद्रा स्फीति की दर पांच फीसदी से अधिक नहीं बढ़ने देने की थी और तीसरी कोशिश रुपये को स्थिर बनाने की थी। आकड़े बताते हैं कि इन्होंने तीनों मोर्चों पर सफलता हासिल की। लेकिन कहते हैं कि अपने फैसलों पर किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करने वाले राजन धीरे धीरे निरंकुश भी होते चले गए। उन्होंने बैंकों पर जबर्दस्त दबाव बनाना शुरू किया। आरबीआई के खजाने से सस्ते पैसे देने के बजाय उन्होंने बैंकों को मुद्रास्फीति से संबंद्ध बांड जारी कर पैसा जुटाने का रास्ता बताया। कॉरपोरेट साख यानी कर्जों पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया। नतीजा बैंकों को महंगे ऑप्शन पर जाने को मजबूर होना पड़ा। कॉरपोरेटों की बैंलेस शीट पूरी तरह बिगड़ कर रह गई और बाजार से मांग गायब हो गई, जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन दर कई बार नकारात्मक वृद्धि दर तक चली गई।

वक्त बीत गया। हालात थोड़े बदल गए। देश में मोदी के नेतृत्व में नई सरकार आ गई। जीडीपी के अच्छे आकड़े भी आ गए, लेकिन राजन की सोंच ज्यादा नहीं बदली। वे अब भी मानते हैं कि भारत की मुद्रा नीति कठोर ही रहनी चाहिए। मार्केट में एक डिसीपलीन बनी रहनी चाहिए। बैंक जब तक अपने एनपीए को कम कर स्टेबिल नहीं हो जाते तब तक एग्रेसिव क्रेडिट पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। राजन ने इसके लिए आगे के और दो साल मांगे हैं जब कंपनियों की बैलेंसशीट दुरूस्त हो जाएगी। यानी तब तक कंपनियां या तो अपने व्यापार को अपने आतंरिक स्रोतों से चलाएंगी या फिर विदेशों से पैसा जुटा कर ही बड़ी परियोजनाएं करेंगी। अपने इस सोंच पर राजन किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसलिए कई बार वह अपनी सीमा से आगे जाकर भी सरकार के कुछ फैसलों की आलोचना कर देते हैं।

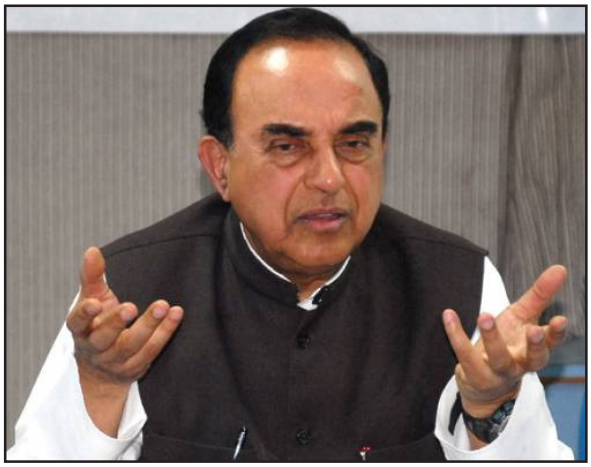

भाजपा नेता सुब्रम्णयम स्वामी कहते हैं 'राजन ऐसा डह्क्टर है, जो बुखार का बेहतर इलाज मरीज को मार देना मानता है।'

राजन प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजदीकी का संबंध रखते हुए भी उनकी ही योजना मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते रहे हैं। वे आज भी हर मंच से कहते हैं कि मेक इन इंडिया के बजाय मेक फॉर इंडिया का कैम्पेन चलाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यदि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन हब बनाया भी तो हमारा माल खरीदेगा कौन? क्योंकि इस समय पूरी दुनिया मंदी की चपेट में है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बना चीन कराह रहा है। राजन की इस साफगोई से भाजपा के कई नेता और मंत्री खफा भी हैं। स्वयं वित्तमंत्री अरूण जेटली इस मामले में राजन की खिंचाई कर चुके हैं। पर राजन को इससे फर्क नहीं पड़ा है।

उनके आरबीआई प्रमुख पद रहने या ना रहने की बहस पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर रोक लगाने की कोशिश की है कि आरबीआई प्रमुख के पद पर फैसला प्रेस के जरिए नहीं समय आने पर ही होगा। यानी सितंबर में ही सरकार यह फैसला सुनाएगी कि राजन रहते हैं या जाते हैं। पर प्रो राजन और एंटी राजन के बीच शब्दों के मिसाइल चलते रहेंगे। प्रो राजन गुट यह प्रचारित करने में लगा है कि यदि उनकी बिदाई आरबीआई से होती है तो विदेशी निवेशको का विश्वास डोल जाएगा और उनके साथ साथ विदेशी निवेश भी बाहर चला जाएगा। जबकि एंटी राजन गुट यह कह रहा है कि यदि वह आरबीआई के गवर्नर बने रहते हैं तो देश की आतंरिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। लोगों को ना तो रोजगार मिलेगा और न कल कारखाने चलेंगे। दोनों गुट सही हो सकते हैं पर राजन दोनों को ही संतुष्ट नहीं कर सकते। ❑❑

उपज है तो दाम नहीं

यह कहानी सूखे आंसूओं की है। इन दिनों शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा, जब आक्रोशित किसानों द्वारा प्याज फेंकने की खबरें पढ़ने को न मिलती हो। हाल की में किसानों ने पांच हजार किलोग्राम प्याज इंदौर के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के बाहर फेंक दिया। कहीं–कहीं तो किसानों ने अपने प्याज मंडियों में की फेंक दिए, जहां वे अपना उत्पाद बेचने आए थे। पचास पैंसे या एक रूपये से ज्यादा हासिल करने में अक्षम इन किसानों के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर भी सार्वजनिक तौर पर इन असहाय किसानों के लिए कोई नहीं बोलता। वे स्वयं अपने आंसू पोछते हैं।

सबसे पहले टमाटर की बात करते हैं। पूरे देश में टमाटर की कीमत में गिरावट आई है। अप्रैल में छपी एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, टमाटर की बंपर फसल होने के कारण महाराष्ट्र के नासिक एवं पुणे के जिलों में कीमतों में गिरावट आई, जिससे किसानों में निराशा फैली और वे विरोध स्वरूप अपनी उपज सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हुए। फरवरी में हैदराबाद से प्रकाशित एक अखबार की रिपोर्ट थी, आवक बढ़ने के कारण नालगोंडा जिले में टमाटर की कीमत में तीन रूपये की गिरावट के कारण किसान संकट में है। यदि आप ध्यान दें, तो ये दोनों खबरे तीन महीने के भीतर छपी हैं, जब टमाटर की फसल मध्य एवं दक्षिण भारत की मंडियों में आई। यदि आप यह सोच रहे हैं कि 2016 ही टमाटर उत्पादकों के लिए बुरा है, क्योंकि अत्याधिक उत्पादन के कारण कीमतों पर असर पड़ा है, तो जरा पूर्व के पांच वर्षों पर ध्यान दीजिए, हर वर्ष आपको यही कहानी देखने को मिलेगी।

अब जरा अगस्त, 2015 में शेयर बाजार में गिरावट को याद कीजिए, जब वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली ने बाजार को आश्वत किया कि सरकार की इस पर नजर है और उन्होंने वैश्विक कारकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रेस कांफ्रेस करके घटनाओं पर नजर रखने के लिए एक समूह का गठन किया। लेकिन जब ऐसा संकट किसानों पर आता

जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय सूखाग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं और दुर्दशा के प्रति सरकार को जगाकर दिखाए कि प्रशासन कितना संवेदनहीन बन गया है। एक अनुमान के मुताबिक, 35 करोड़ लोग गंभीर सूखे की चपेट में हैं, लेकिन सरकार और मुख्यधारा के मीडिया का एक हिस्सा इस गंभीर संकट से बेखबर था।

– देविंदर शर्मा

है और वह भी तब, जब वर्ष दर वर्ष फसलों की कमतें गिरती जाती हैं, तो कभी नहीं देखा गया कि संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए वित्तमंत्री ने कोई पहल की हो।

बेशक मैं जानता हूं कि टमाटर ऐसी फसल नहीं है, जिसमें किसी निर्वाचित सरकार को गिराने की क्षमता हो, लेकिन किसानों के संकट के प्रति उदासीन रहने का कोई कारण नहीं है। कीमत में गिरावट किसानों की मेहनत को बर्बाद कर देता है। अर्थशास्त्री इस मांग और आपूर्ति की स्थिति का परिणाम कह सकते हैं, लेकिन यहां यह सवाल पूछे जाने की जरूरत है कि इसमें किसानों की क्या गलती है कि उन्होंने टमाटर की खेती में निवेश किया। इस वर्ष टमाटर के उत्पाद वाले इलाकों में बड़ पैमाने पर टमाटर उत्पादक किसानों ने (छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में दस हजार हेक्टेयर से ज्यादा) अपनी फसलें खेतों में ही छोड़ दी, क्योंकि टमाटर तोड़ने और उसकी पैकेजिंग पर आने वाला खर्च निकलना भी मुश्किल था।

यही हाल प्याज की कीमतों का हुआ। तीन साल की उथल–पुथल के बाद, जब प्याज की कीमतें आसमान छू रही थी, तो मीडिया के शोर–शराबे के बाद सरकार को मजबूरन प्याज की कीमतों को कम करने के लिए कई कदम उठाने पड़े। लेकिन इस वर्ष कृषक समुदाय के आंसू पोछने कोई सामने नहीं आया। यहां तक सजग मीडिया भी नहीं, जिसने प्याज की कीमत में 25 से 30 फीसदी की वृद्धि के बाद आसमान सिर पर उठा लिया था, वह भी बिल्कुल खामोश रहा, जबकि प्याज की कीमतें गिरकर तीस पैसे प्रति किलो पर आ गई। प्याज उत्पादक किसानों की दुर्दशा मीडिया को प्रभावित करने में अक्षम है, जो आम तौर पर प्याज की कीमत से संबंधित मामलों में अति संवेदनशील रहता है।

फरवरी में ही प्याज की कीमतों में

अत्यधिक उत्पादन के कारण नासिक की मंडियों में प्याज का औसत थोक मूल्य दो वर्ष के न्यूनतम स्तर 700 रूपये प्रति क्विंटल पर आ गया है।

गिरावट की खबरे आने लगी थी। एक अंग्रेजी दैनिक ने लिखा, अत्यधिक उत्पादन के कारण नासिक की मंडियों में प्याज का औसत थोक मूल्य दो वर्ष के न्यूनतम स्तर 700 रूपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। पिछले एक सप्ताह में प्याज की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है, इससे उन किसानों की चिंता बढ़ गई है, जो कीमत स्थिर होने तक प्याज को रखने की स्थिति में नहीं है। अप्रैल में एक अंग्रेजी साप्ताहिक ने बताया कि मध्य प्रदेश के नीमच में प्याज की कीमत 30 पैसे प्रति किलोग्राम पर आ गई है। पिछले 13 मई को एक अंग्रेजी दैनिक ने लिखा कि लासुर के थोक बजार में 450 किलोग्राम छोटे प्याज बेचने पर मात्र 175 रूपये मिलने के बाद रवीन्द्र मधिकर नामक किसान सदमे में है। मैं अक्सर सोचता था कि किसान खुदकुशी करने का अतिवादी फैसला क्यों करते है। लेकिन इस सौदे के बाद में खुद हताश महसूस कर रहा हूं।

मैं समझ सकता हू कि इस वर्ष प्याज शहरी उपभोक्ता की आंखों में आंसू नहीं लायेंगे, लेकिन क्या यह सिर्फ मांग और आपूर्ति के कारण हुआ? एक तरफ जहां मीडिया का रवैया पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, वहीं कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की उदासीनता चौंकाती है। मई, 2015 में सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए 500 करोड़ रूपये का कोप बनाया था, ताकि वर्ष 2015–17 के दौरान कृषि–बागवानी के उत्पादों के मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिए बाजार को समर्थन मिल सके, लेकिन संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए कोई पहल नहीं दिखाई दे रही है।

चूंकि मूल्य स्थिरीकरण कोष का उद्देश्य प्याज एवं आलू के मूल्यों पर नियंत्रण रखना है, इसलिए में समझता था कि प्याज उत्पादक किसानों की मदद करने के लिए उन्हें बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य के अंतर की भी भरपाई की जानी चाहिए। लेकिन तुरंत ही मैंने महसूस किया कि मूल्य स्थिरीकरण कोष का उद्देश्य यह नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य महंगाई बढ़ने पर किसानों या कृषक संगठनों से उत्पादों की सीधे खरीद करना है, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर उसे उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए जब मूल्यों में गिरावट आई है, तो किसानों को खुद की अपने आंसू पोछने के लिए छोड़ दिया गया है। ❑❑

चाबहार एवं भारत-ईरान सहयोगः

एक चिर अपेक्षित रणनीतिक पहल

भारत और ईरान के बीच आर्थिक व रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास और एक एल्युमीनियम संयंत्र लगाने के समझौते अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और ईरानी राष्ट्रपति हसन रोहानी के बीच तेहरान में चाबहार पोर्ट के विकास हेतु हुये समझौते के अंतर्गत भारत इस बंदरगाह में 50 करोड़ डालर का निवेश करने जा रहा है। ईरान और भारत के बीच कई अन्य क्षेत्रों में भी करोड़ों डालर के और भी द्विपक्षीय समझौते भी हुए। दक्षिण ईरान के चाबहार बंदरगाह के मार्ग से अब भारत पाकिस्तान को बाईपास कर मध्य एशिया तक पहुंच सकेगा।

भारत के कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इसलिये भारत सरकार चाहती है कि मध्य एशिया से पाइप लाइन के जरिए तेल और गैस भारत तक लाया जाये। लेकिन, पाइपलाइन के शुल्क और उसकी सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई विश्वसनीय आश्वासन नहीं मिला।

– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

भारत के कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इसलिये भारत सरकार चाहती है कि मध्य एशिया से पाइप लाइन के जरिए तेल और गैस भारत तक लाया जाये। लेकिन, पाइपलाइन के शुल्क और उसकी सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई विश्वसनीय आश्वासन नहीं मिला। इसलिये अब भारत पाइप लाइन से चाबहार से ईंधन ला सकता है और वहां से आगे इन जहाजों के द्वारा भारत लाया जा सकता है। अब भारत को इसके लिये पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन समझौतों में भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित कराने वाली रेल लाइन बिछाने का समझौता भी शामिल है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की रेल कंपनी इरकॉन समझौते के अधीन ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान तक 500 किमी. लंबी रेल लाइन बिछायेगी जिसपर 1.6 अरब डालर की लागत आने का अनुमान है। यह रेल लाइन ईरान के दक्षिणी तटीय क्षेत्र से अफगानिस्तान के जाहेदान तक बिछाई जाएगी।

चाबहार बंदरगाह जो ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान–बलुचिस्तान प्रांत में पड़ता है। इसलिये यह रणनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के पश्चिमी तट से फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित इस बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह बंदरगाह पाकिस्तान स्थित ग्वाडर बंदरगाह से 60 मील की दूरी पर ही स्थित है, जहां चीन अपना नौसैनिक अड्डा विकसित कर रहा है। यहां से ग्वाडर की हलचलों पर भी भारत दृष्टि रख सकेगा। जबकि यहां भारत अब ईरान, अफगानिस्तान, व मध्य एशियाई देशों तक व्यापार बढ़ाने व वहां से ऊर्जा आयातों को बढ़ाने में तो सफल हो सकेगा और इसके लिये पाकिस्तान से रास्ता मांगने की जरूरत नहीं होगी।

भारत द्वारा 2009 में निर्मित जारंज–देलारम सड़क अफगानिस्तान के राजमार्ग तक पहुंच प्रदान कर सकती है जो अफगानिस्तान के चार प्रमुख शहरों– हेरात, कंदहार, काबुल और मजार–ए–शरीफ तक पहुंच प्रदान करेगा। ऐसी भी सूचनायें है कि भारत अफगानिस्तान

के अन्दर एक और सड़क नेटवर्क के निर्माण के लिए वित्तपोषण करेगा जिससे ईरान अपेक्षाकृत छोटे मार्ग के जरिए ताजिकिस्तान तक जुड़ने में मदद मिलेगी। चाबहार पाकिस्तान में चीन द्वारा परिचालित ग्वादार बंदरगाह से करीब 100 किलोमीटर दूर है जो चीन की 46 अरब डालर के निवेश से चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा विकसित करने की योजना का अंग है और इसका उद्देश्य फारस की खाड़ी तक चीन की सामारिक पहुंच विकसित करना है इस दृष्टि से भी चाबहार भारत के लिये महत्वपूर्ण है, इसीलिये इस समझौते पर पाकिस्तान में जो हताशा दिखायी दे रही है, वह स्वाभाविक है। इस्लामाबाद को लगता है कि अगर मध्य एशिया से कोई भी चीज जमीन के जरिए भारत तक जाती तो उसे ही इसका राजस्व मिलना था। इसलिये चाबहार समझौते से पाकिस्तान का निराश होना स्वाभाविक है। दूसरा कारण यह भी है कि अफगानिस्तान तक कभी भी भारी साज काबुल को लेकर भारत और पाकिस्तान की प्रतिस्पर्धा किसी से छुपी नहीं है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान के ऊपर से उड़े बिना भारी साजो सामान अफगान धरती पर पहुंचा सकता है और यह बात इस्लामाबाद को यह बात सर्वाधिक चुभ रही है। भारत व अफगानिस्तान के बीच इस सुरक्षा संबंध भी मजबूत होंगे। इसलिये चीन व पाकिस्तान दोनों ही इस समझौते से प्रसन्न नहीं है। चीन तो स्वयं चाबहार समझौते का इच्छुक था।

इस समझौते के व्यापक आर्थिक व रणनीतिक महत्व के कारण ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते को ''एक महत्वपूर्ण घटना बताया।'' उन्होंने कहा, ''इस बड़ी पहल से इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। हम आज हुए इन समझौतों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं।'' इसी परिप्रेक्ष्य में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी कहा है कि ''चाबहार दोनों महान देशों के बीच सहयोग का काफी बड़ा प्रतीक बन सकता है। यह भारत और अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के देशों तथा सीआईएस राष्ट्रों और इसके साथ ही पूर्वी यूरोप के बीच संपर्क बिंदु की भूमिका निभा सकता है।'' चाबहार बंदरगाह से इस संपूर्ण क्षेत्र में जुड़े कई देशों को लाभ होगा। इसे और स्पष्ट करते हुये रूहानी ने यह भी कहा है कि जब हम दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो हमारा आशय ईरान और इसके आसपास देशों से है। मैं इस क्षेत्र की 40 करोड़ की आबादी की बात कर रहा हूं और इसके अलावा मैं 1.2 अरब की आबादी वाली ताकत भारत की भी बात कर रहा हूं। ईरान और अफगानिस्तान की भागीदारी के साथ त्रिपक्षीय परिवहन एवं पारगमन समझौते के बारे में बात करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा, कि इससे भारत, ईरान और अफगानिस्तान के लिए नया मार्ग खुलेगा। मोदी ने यह भी कहा कि भारत और ईरान की इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और संपन्नता में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।'' इस अवसर पर ईरान के राष्ट्रपति, रूहानी को भारत यात्रा का आमंत्रण देते हुए भी मोदी ने कहा है कि हम दोनों देशों के बीच संपर्क अधिक से मजूबत बनाने को उत्सुक हैं। भागीदारी के इस एजेंडे और सहयोग को दायरे को वास्तविकता का करार देते हुए, मोदी ने कहा कि ''आज जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उनसे हमारी रणनीतिक भागीदारी में एक नया अध्याय जुड़ा है। विस्तृत व्यापारिक संबंध, रेलवे समेत संपर्क सुविधाओं के क्षेत्र में गहरे संबंध तथा तेल एवं गैस, उर्वरक, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में भागीदारी के विस्तार कुल मिलाकर हमारे आर्थिक संबंधों को बल मिला है।''

अन्य समझौते

- ईरान के विदेश मंत्रालय के स्कूल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस तथा भारत के विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) के सहयोग का समझौता।
- ईरान के विज्ञान, शोध और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच सरकारी व्यवस्था के बारे में समझौता।
- भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा ईरान के राष्ट्रीय पुस्तकालय के बीच भी एमओयू हस्ताक्षरित हुआ हैं।
- संस्कृति मंत्रालय तथा ईरान के संस्कृति तथा इस्लामिक दिशानिर्देशन मंत्रालयों के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए सरकारी व्यवस्था संबंधी हुआ समझौता दोनों देशों के बीच निकटता लायेगा।
- ईरान के इस्लामिक संस्कृति तथा संबंध संगठन तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध, परिषद के बीच भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुये है।

चाहबहार बंदरगाह के लिए जॉइंट वेंचर

चाबहार परियोजना, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह के लिए पहला विदेशी उद्यम होगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और इसकी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल में साठ प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि कांडला पोर्ट के पास शेष 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जबकि चीन पाकिस्तान में ग्वाडर व श्रीलंका में हम्बन तोटा बंदरगाहों का विकास कर चुका है।

भारत–ईरान के बीच खुले सहयोग के इस नवीन अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण करार ईरान के दक्षिणी तट पर चाबहार बंदरगाह के पहले चरण का विकास। इसे भारत के साथ एक संयुक्त उद्यम के जरिए विकसित किया जाएगा। इसमें चाहबहार बंदरगाह के दो टर्मिनलों और पांच गोदी का 10 साल तक विकास एवं संचालन किया जाएगा। इसके लिए एक्जिम बैंक और ईरान के पोर्ट्स एण्ड

मैरीटाइम आर्गनाइजेशन के बीच 15 करोड़ डॉलर के ऋण के लिए किया एमओयू समझौता भी शामिल है। एक्जिम बैंक और सैंट्रल बैंक ऑफ ईरान के बीच एक स्वीकृति वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किए गए जिसमें स्टील रेलों के आयात और चाबहार बंदरगाह के क्रियान्वयन के लिए 3,000 करोड़ रुपए तक की ऋण उपलब्धता के लिये स्वीकृति दी गई है।

रेल लाइन बिछाने के लिए भारत की इरकॉन ने ईरान की कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांस्पोर्ट एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी (सीडीटीआईसी) के साथ आपसी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इरकॉन के प्रबंध निदेशक मोहन तिवारी और ईरान के रेल उपमंत्री पाउरसैयद अघेई ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पिछले 15 साल के दौरान ईरान की यात्रा करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं।

नाल्को स्थापित करेगा अल्युमिनियम प्लांट

सार्वजनिक क्षेत्र की नाल्को ने चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र में 5 लाख टन क्षमता का एल्युमीनियम स्मेल्टर लगाने की संभावना के लिए एमओयू पर दस्तखत किए हैं। यह स्मेल्टर तब लगाया जाएगा जब ईरान सस्ती प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराएगा। ईरान के एक्सपोर्ट गारंटी फंड तथा भारत के एक्सपोर्ट गारंटी कारपोरेशन के बीच एमओयू हुआ है। इन दस्तावेजों में दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच नीति निर्माण के लिए वार्ता तथा शोध संस्थानों के बीच परिचर्चा के लिए एमओयू पर दस्तखत भी शामिल है।

अफगानिस्तान में अत्यंत अनुकूल प्रतिक्रिया

अफगान मीडिया ने भी तेहरान में हुए इस चाबहार बंदरगाह समझौते की मंगलवार 24 मई 2016 को अत्यंत खुलकर सराहना की है। यह इस क्षेत्र में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग एवं क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता बढ़ाने की दिशा में एक छलांग है, ने इस पर टिप्पणी करते हुये लिखा है कि समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, "भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सोमवार को ईरान की राजधानी तेहरान में चाबहार पोर्ट को विकसित करने एवं भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया एवं कोकेशियाई देशों से जोड़ने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।" इसी क्रम में समाचार पत्र 'डेली अफगानिस्तान' ने अपने संपादकीय

चाबहार बंदरगाह के क्रियान्वयन के लिए 3,000 करोड़ रुपए तक की ऋण उपलब्धता के लिये स्वीकृति दी गई है।

में कहा है कि चाबहार बंदरगाह करार इस क्षेत्र में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग एवं शांति एवं स्थिरता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

अखबार ने कहा है, "चाबहार पोर्ट विकसित होने से मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ने वाली सड़कों के चौराहे के रूप में अफगानिस्तान की ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक भूमिका फिर से प्रचलन में आ जाएगी।" अखबार ने इसे विस्तार देते हुए यह स्पष्ट किया है, "चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के व्यापारियों की पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर निर्भरता भी कम हो जाएगी।"

इसी बात को एक अन्य अखबार 'डेली मांडेगार' ने भी चाबहार बंदरगाह करार को कराची बंदरगाह पर अफगानिस्तान की निर्भरता कम करने की दिशा में मील का पत्थर करार दिया है। इस पर द्रुत गति से काम करते भारत 18 महीनों के अंदर चाबहार बंदरगाह को डेवलप करेगा और इसके बाद सीधे ईरान से भारत व्यापार कर सकेगा और इसी पोर्ट के जरिए भारत अपना माल अफगानिस्तान भी भेज पायेगा। इस प्रकार अफगानी संचार माध्यमों में भी इस समझौते को लेकर भारी उत्साह व आशा दिखाई देती है।

बंदरगाह समझौते पर भारत की लम्बे समय से दृष्टि

इस बंदरगाह के विकास के लिए हालांकि 2003 में ही भारत और ईरान के बीच प्रारंभिक समझौता हो गया था। परमाणु कार्यक्रमों के चलते ईरान पर पश्चिमी देशों की ओर से पाबंदी लगा दिए जाने के बाद इस प्रोजेक्ट का काम धीमा हो गया। जनवरी 2016 में ये पाबंदियां हटाए जाने के बाद भारत ने इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। मोदी सरकार ने फरवरी 2016 में ही चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 150 मिलियन डॉलर के क्रेडिट लाइन को हरी झंडी दे दी थी। चाबहार से ईरान के मौजूदा रोड नेटवर्क को अफगानिस्तान में जरांज तक जोड़ा जा सकता है जो बंदरगाह से 883 किलोमीटर दूर है। 2009 में भारत द्वारा बनाए गए जरांज–डेलारम रोड के जरिये अफगानिस्तान के गारलैंड हाइवे तक आवागमन आसान हो जाएगा। इस हाइवे से अफगानिस्तान के चार बड़े शहरों–हेरात, कंधार, काबुल और मजार–ए–शरीफ तक सड़क के जरिये पहुंचना आसान होता है।

फारस की खाड़ी के बाहर बसे इस बंदरगाह तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट से पहुंचना आसान है। इस बंदरगाह के जरिये भारतीय सामानों के ट्रांसपोर्ट का खर्च और समय एक तिहाई कम हो जाएगा। अरब सागर में चीन को तो पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट के विकास के माध्यम से भारत के विरूद्ध एक बड़ा सामरिक ठिकाना उपलब्ध मुहैया कराया है। ❑❑

जब ठेंगड़ी जी ने हिसंक संघर्ष को तर्कों से काटा

इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की स्थिति घोषित करके भारत में अपना तानाशाही शासन कायम किया। कम्युनिस्ट नेताओं को छोड़कर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को मीसा (आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव अधिनियम) के तहत हिरासत में ले लिया गया। जे.ए.के गोपालन और ज्योति बसु जैसे कम्युनिस्टों को भी इंदिरा गांधी ने आलोचना के बदले जेल में डाल दिया। जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

कुछ ही दिनों में पूरा प्रशासन और न्यायपालिका भी इंदिरा गांधी के इशारों पर काम करने लगे। तीन प्रमुख न्यायधीशों के दावे को दरकिनार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में ए.एन.रॉय को पदोन्नत किया गया जिसने नागरिक अधिकारों के हनन और राज्यप्रायोजित दमन का समर्थन किया। जेल के अंदर बंद नेताओं और बाहर खड़े उनके समर्थकों के बीच का हर तरह संवाद खत्म कर दिया गया। समाचार पत्रों पर भी पाबंदी लगा दी गई और देश में एक तरह से भय एवं दहशत का वातावरण फैला दिया गया। मुझे नानाजी देशमुख, जिन्हें जयप्रकाश नारायण ने अपने हिरासत में लिए जाने से ठीक पहले लोक संघर्ष समिति का संचालक बनाया था, का पत्र मिला। हस्तलिखित इस पत्र में नानाजी देशमुख ने हमें बताया कि किस तरह इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा से पहले सिद्धार्थ शंकर रॉय और रशियन राजदूत से सलाह–मशवरा किया। उड़ीसा का मुख्यालय आगरा स्थांतरित कर दिया गया, और यह सलाह दी गई कि उन सभी लोगों के नाम दीवारों पर लिखें जाए जो मीसा के तहत गिरफ्तार किए गये हैं। चूंकि मुझे आपातकाल की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद लोक संघर्ष समिति उड़ीसा का प्रमुख बनाया गया था और मैं राज्य

कुछ ही दिनों में पूरा प्रशासन और न्यायपालिका भी इंदिरा गांधी के इशारों पर काम करने लगे। तीन प्रमुख न्यायधीशों के दावे को दरकिनार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में ए.एन.रॉय को पदोन्नत किया गया जिसने नागरिक अधिकारों के हनन और राज्यप्रायोजित दमन का समर्थन किया।
– सरोज मित्र

भारतीय मजदूर संघ का महासचिव था, मैंने उड़ीसा के राजनीतिक नेताओं से संपर्क साधना शुरू किया। उनमें से कई लोग सरकार से सीधे टकराने से बचना चाहते थे। चूंकि बीजू पटनायक, जिनके सीधे संपर्क में था, उड़ीसा के बाहर गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए मैं उड़ीसा के सर्वोदय नेता और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नबकृष्ण चौधरी की पत्नि मालती चौधरी से मिला। नबकृष्ण चौधरी को भी बरिपदा में गिरफ्तार कर लिया गया था। हमनें यह तय किया कि कटक के काठीजोडी नदी के तट पर 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती मनायेंगे। कलकत्ता से पोस्टर और पर्चे मंगाये गये और बाटे गये। मैं भी सितंबर 1975 में गिरफ्तार हो गया। लेकिन काठीजोडी नदी पर प्रदर्शन निकाला गया और योजना के अनुसार बैठक भी हुई।

हजारों स्वयंसेवकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और देश भर में गिरफ्तारियां दी। दस हजार से अधिक स्वयंसेवकों के खिलाफ जारी वारंट तामिल नहीं हो सका, क्योंकि वे लोग भूमिगत होकर काम कर रहे थे। इस बीच 1976 में कुछ लोग तंग आकर हिंसा आधारित आंदोलन की बात करने लगे थे, उनमें से ही एक थे बेकुठ लाल शर्मा (प्रेम जी)। प्रेम जी तबके संघर्ष समिति के प्रमुख दत्तोपंत ठेंगडी से इस विषय पर बहस कर रहे थे। उसका परिणाम यह हुआ कि ठेंगड़ी जी ने क्रांति पर एक बहुत की बढ़िया लेख लिखा, जिसको कार्यकर्ताओं के बीच बांटा गया। रिवोलूशन नाम की पुस्तिका में किए गए विश्लेषण में दुनिया भर में हुई हिसंक गतिविधियों के बाद सरकार के गठन और उसका वहां के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले असर का विस्तृत विवरण दिया गया था। उसमें हिंसा प्रभावित जन संघर्ष के बजाए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन को समर्थन दिया गया था। ऐसे ही पत्र जेल के अंदर से भी आए जिसमें कहा गया कि यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। उदाहरण दिया गया कि जिस तरह अफजल खानद अपना धेर्य खोने के बाद शिवाजी के प्रभाव वाले जंगल क्षेत्र में घुस गया, उसी तरह हमें इंदिरा गांधी को भी अपने रणनैतिक लक्ष्य के करीब आने देना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए।

मैंने अपने साथ कियोझर जेल में मीसा के तहत बंद साथी कैदियों को यह पत्र दिखाया। उनमें से दो जमाते इस्लामी से जुड़े हुए थे। वे बहुत विचलित थे और कह रहे थे कि कौन इतना लंबा जेल में इंतजार करेगा। उसी पत्र में अकबर और बीरबल की भी एक कहानी लिखी हुई थी। अकबर ने सूर्यास्त से पहले यमुना के किनारे टहलते हुए बीरबल से पूछा कि ईश्वर क्या कर रहा है। इस पर बीरबल बालो 'जहापनाह एक यह एक बेहद सरल सवाल है इसमें मेरे जवाब की जरूरत नहीं है'। तभी गायों को चराने के बाद वापिस लौटते हुए एक बच्चे पर अकबर की नजर पड़ी। अकबर ने पूछा 'क्या यह बच्चा मेरे सवाल का जवाब दे सकता है'। बीरबल ने कहा 'जी हां बिल्कुल'। जब बच्चा पास आया तो अकबर ने वहीं सवाल पूछा और कहा कि अगर वह जवाब देगा तो वह उसे उपहार देगा। उस चरवाहे बच्चे ने अकबर से कहा कि क्या वह उसे गुरू मानने के लिए तैयार होगा? और अगर हां तो वह गुरू दक्षिणा देगा। अकबर ने बच्चे की बात मान ली और उसे अपने गले से सोने की चैन निकालकर दे दी। फिर अकबर ने पूछा 'ईश्वर क्या कर रहा है'। बच्चे ने कहा 'ईश्वर वहीं कर रहा है जो आपने किया है' और चला गया। अब बीरबल ने कहा कि बच्चे ने सही जवाब दिया कि ईश्वर एक चरवाहे को राजा बना रहा है और राजा को चरवाहा।

आपातकाल मार्च 1977 में हटा दिया गया उसके बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी तरह से हार हुई। हम लोग 17 महीनें बाद जेल से बाहर आए। धैर्य की जीत हुई। ❑❑

हजारों स्वयंसेवकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और देश भर में गिरफ्तारियां दी। 10,000 से अधिक स्वयंसेवकों के खिलाफ जारी वारंट तामिल नहीं हो सका, क्योंकि वे लोग भूमिगत होकर काम कर रहे थे।

बंद होता कर चोरी का मॉरिशस रास्ता

मॉरिशस के साथ लगभग तीन से भी आर्थिक दशक पुरानी दोहरे कर अवंचन संबंधी संधि (डीटीएटी) में संशोधन के साथ ही विदेशी निवेशकों के लिए एक टैक्स स्वर्ग के रास्ते बंद हो रहे हैं और साथ ही बंद हो रहा है कर चोरी का एक बड़ा मार्ग। गौरतलब है कि भारत ने मॉरिशस के साथ वर्ष 1982 में एक समझौता किया था, जिसके अनुसार यदि मॉरिशस के रास्ते कोई विदेशी निवेश प्राप्त होता है तो उसपर होने वाले पूंजीगत लाभों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस समझौते में यह प्रावधान था कि पूंजीगत लाभों पर या तो मॉरिशस में टैक्स दिया जाए या भारत में। मॉरिशस में पूंजीगत लाभों पर कोई टैक्स नहीं था, ऐसे में भारत में भी निवेशकों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब नए संशोधनों के अनुसार 1 अप्रैल 2017 के बाद खरीदे गए शेयरों पर होने वाले पूंजीगत लाभों पर पहले दो साल भारत में पूंजीगत लाभों पर लगने वाले टैक्स का आधा (50 प्रतिशत) वसूला जाएगा और 2019 के बाद ऐसे लाभों पर पूरा पूंजीगत लाभ कर लगेगा।

भारत ने मॉरिशस के साथ वर्ष 1982 में एक समझौता किया था, जिसके अनुसार यदि मॉरिशस के रास्ते कोई विदेशी निवेश प्राप्त होता है तो उस पर होने वाले पूंजीगत लाभों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस समझौते में यह प्रावधान था कि पूंजीगत लाभों पर या तो मॉरिशस में टैक्स दिया जाए या भारत में। मॉरिशस में पूंजीगत लाभों पर कोई टैक्स नहीं था, ऐसे में भारत में भी निवेशकों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था।

– डॉ. अश्वनी महाजन

गौरतलब है कि कर चोरी के उद्देश्य से कंपनियां अपने पैसे को घुमाकर मॉरिशस के रास्ते से लाती थी। पिछले सालों में ऐसे कई मामले सामने आए, जिसमें स्पष्ट हो रहा था कि कंपनियों ने जानबूझ कर कर चोरी के उद्देश्य से निवेश के लिए मॉरिशस का रास्ता चुना। इसमें सबसे ज्यादा बदनाम मामला वोडाफोन का रहा। वोडाफोन कंपनी ने मॉरिशस के रास्ते पैसा भारत में कार्यरत एक विदेशी कंपनी 'हच' में निवेश किया और 11 अरब डालर के पूंजीगत लाभ पर टैक्स की चोरी कर ली। कानूनी दांवपेंच में हालांकि कंपनी भारतीय इन्कम टैक्स विभाग से जीत गई, लेकिन उसके बाद कानूनी बदलाव के चलते कंपनी पर भारतीय आयकर विभाग का दावा अभी भी बना हुआ है। यही नहीं, हाल की में प्रकाश में आये अगस्ता वेस्टलैंड की रिश्वत का भी संबंध मोरिशस रूट से है। इससे पहले एयर एशिया (भारत में नागरिक उड़ययन के क्षेत्र में आई कंपनी) पर भी मोरिशस रूट से कालाधन लाने का मामला सामने आ चुका है। 2001 के शेयर घोटाले के दौरान, मारिशस के साथ हुई यह संधि, सबसे ज्यादा चर्चा में रही, जिसमें घोटाले में लिप्त लोगों ने इस मार्ग के माध्यम से घोटाले को अंजाम दिया था। इसके अलावा कई ऐसे मामले मारिशस मार्ग से जुड़े हैं, जिनके कारण देश को राजस्व में भारी हानि हुई है।

मॉरिशस संधि में संशोधन के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह संधि अब पैसे को घुमाकर कर चोरी की त्रास्दी के विषय का समाधान कर पाएगी और इससे राजस्व का नुकसान तो रूकेगा ही और दोनों देशों में कर न देने की स्थिति भी नहीं रहेगी। निवेश का प्रवाह व्यवस्थित हो जाएगा और कर मामलों में पारदर्शिता बढ़ने के कारण कर चोरी भी रूकेगी। लेकिन 2017 से पहले हुए निवेश पर अभी भी पूंजीगत लाभ पर टैक्स प्रभावी नहीं होगा।

यूं तो भारत सरकार ने बड़ी संख्या में दोहरे कर अवंचन की संधियां दूसरे मुल्कों के साथ की हुई हैं, जिसके लिए औचित्य तो यह दिया जाता रहा है कि इसके रास्ते विदेशी निवेश का आना सुगम हो जायेगा, लेकिन इन संधियों के कारण भारत को लाखों करोड़ रूपये के राजस्व का तो नुकसान हुआ ही, साथ ही देश में वित्तीय अनुशासन की भी धज्जियां उड़ती रही।

हाल ही में दुनिया के 300 प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक नेताओं को पत्र लिखकर 'टैक्स स्वर्गों' को समाप्त करने की गुहार लगाई है और कहा है कि इनको जारी रखने का कोई आर्थिक औचित्य नहीं है। पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में थॉमस पिकेटी (प्रसिद्ध आर्थिक लेखक), अंगूस डीटनर (2015 के नोबेल पुरस्कार विजेता), आदि प्रमुख अर्थशास्त्री शामिल हैं।

पत्र में कहा गया है कि 'टैक्स हैवनों' का लाभ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमीर लोगों को ही हो रहा है और इनसे किसी संपत्ति का सृजन नहीं होता। गरीबों की कीमत पर अमीरों को फायदा पहुंचाने वाले 'टैक्स हैवन' दुनिया में असमानता बढ़ा रहे हैं।

क्या दिया जाता है औचित्य?

बदनाम मोरिशस संधि को बदलने की मांग कई वर्षों से हो रही थी, लेकिन इससे पूर्व की सरकारें इस पर कान नहीं धर रही थी। तर्क यह दिया जाता था कि चूंकि बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश इस मार्ग द्वारा देश में आ रहा है, इसमें कोई फेरबदल विदेशी निवेश को प्रभावित कर सकता है। मारिशस संधि का समर्थन करने वाले लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर आर्थिक नीति के आधार पर औचित्यपूर्ण ठहरा रहे थे। यह कहा जा रहा था कि हिन्द महासागर में भारत के सामरिक हितों के मद्देनजर यह संधि महत्वपूर्ण है। उनका यह भी कहना है कि इस संधि के कारण देश को भारी मात्रा में विदेशी निवेश भी प्राप्त होता है। उनका कहना है कि इस संधि में कोई भी परिवर्तन भारत के आर्थिक हितों के खिलाफ होगा।

2017 और 2019 के बीच पूंजीगत लाभों पर टैक्स सामान्य से आधा होगा और 2019 के बाद ही पूरा टैक्स लग पाएगा।

मंगलकारी होगी टैक्स हैवनों की समाप्ति

आज जब यह स्पष्ट हो रहा है कि टैक्स हैवनों से बड़ी कंपनियों और अमीर लोगों के अतिरिक्त किसी का भला नहीं हो रहा, और यह टैक्स स्वर्ग कर चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे विकासशील देशों के राजस्व प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण इन देशों की सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सामाजिक सेवाओं के लिए खर्च बढ़ाने में असमर्थ हो रही हैं, इन टैक्स हैवनों पर अंकुश लगाना इन मुल्कों के गरीबों और वंचितों के लिए मंगलकारी है। वोडाफोन द्वारा 12 हजार करोड़ रूपए की कर चोरी और ऐसे ही कई अन्य कंपनियों द्वारा करों की चोरी, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा करों की चोरी, अपराधियों द्वारा इन टैक्स स्वर्ग मार्गों का अनैतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल आदि तमाम ऐसे कारण हैं, जो टैक्स स्वर्गों को समाप्त करने के लिए औचित्य प्रदान करते हैं। अभी केवल मॉरिशस के साथ संधि में ही बदलाव किया गया है। मॉरिशस के समान ही कई अन्य देशों के साथ भी दोहरे कर आवंचन की संधियां अभी बदस्तूर जारी है, जिनमें से स्लोवेनिया समेत कुछ में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। जरूरत इन बात की है कि मॉरिशस के साथ इस संधि में जिस प्रकार से संशोधन हुआ है, उसी तर्ज पर अन्य देशों के साथ भी संधियों में बदलाव हो।

आधा–अधूरा कदम है मॉरिशस संधि में बदलाव

इस संदर्भ में मॉरिशस के साथ हुई तीन दशक से भी पुरानी संधि में बदलाव केवल एक छोटा सा, लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। कई लोग इस बदलाव को पर्याप्त नहीं मानते, क्योंकि यह 2017 से लागू होगा और 2017 से पहले हुए निवेशों पर कैप्टिल गेन टैक्स से छूट जारी रहेगी। संधि में ग्रैंडपेरेंटिंग का प्रावधान इस संधि के आलोचकों को सही नहीं लगता, क्योंकि 2017 से पहले होने वाले तमाम निवेशों के आगे इस्तेमाल से होने वाले पूंजीगत लाभों को भी कर से छूट जारी रहेगी। 2017 और 2019 के बीच पूंजीगत लाभों पर टैक्स सामान्य से आधा होगा और 2019 के बाद ही पूरा टैक्स लग पाएगा। इस बदलाव को एक अन्य कारण से भी अपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह केवल शेयरों की खरीद पर होने वाले पूंजीगत लाभों पर ही लागू होगा और मार्जिन एवं डेग्विेटिव ट्रेडिंग पर यह लागू नहीं माना जाएगा। ❑❑

सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति संभव

गत सितंबर 2015 मास में लंदन की एक बड़ी सभा में बोलते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य–पुत्र देशों के एक बड़े गठबंधन की घोषणा की। दुनिया के 120 देश, जहां सौर उर्जा बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, ऐसे देशों को गठबंधन को सौर उर्जा का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नाम दिया गया और उसका केंद्र भी भारत में गुरू ग्राम में घोषित किया। इससे सौर उर्जा का योगदान विषय की तरह वैश्विक महत्व घोषित हो गया। भारत में यह बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ न केवल पर्यावरण–हितैषी उर्जा का स्त्रोत है बिल्कुल अर्थतंत्र को भी बड़ी गति देने वाला है।

दुनिया में प्रति व्यक्ति आय (सर्वाधिक) खाड़ी के देशों जैसे संयुक्त अरब अमेरात, सउदी अरब, बहरीन की है। इन देशों के पास न तो कोई बड़ा निर्माण उद्योग है, न उनके पास खेती है और न ही अनुसंधान एवं विकास का कार्य, किंतु अपनी जमीन के नीचे अथाह उर्जा शक्ति यानि तेल के कारण वे दुनिया के समृद्वतम देश बने हैं। गत 100–125 वर्षों में तेल आधारित ऑटोमोबाइल व अन्य शक्ति खपत केंद्र इतने विकसित हुए कि इन्होंने मुंह मांगे दाम लिए। तेल उत्पादित देशों ने अपना गठजोड़ (ओपेक) बना कीमतें निर्धारण तंत्र अपने पास रखा एवं सारी दुनिया से पैसे का बहाव उधर मुड़ गया।

यदि इन दोनों देशों को प्रकृति ने जमीन के नीचे उर्जा शक्ति दी है तो यह उर्जा भारत को आसमान से दी है, सूर्य के रूप में। हम तो अपने को कहते की सूर्य–पुत्र हैं। किंतु भारत ने अपनी इस प्रकृति प्रदत्त संपदा को पहचानने में बहुत देर की। किंतु 'देर आए दुरूरस्त आए' के अनुसार भारत में अब इस उर्जा शक्ति स्त्रोत पर तेजी से कार्य हो रहा है।

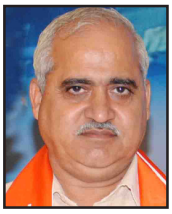

भारत में इस समय कुल मिलाकर 280 गीगावाट बिजली पैदा की जाती है। इससे कोयले के Thermal Plant, छोटे–बड़े hydro dam, तेल–डीजल से चलने वाले जनरेटर, न्यूक्लियर व renewable सभी प्रकार के मिलाकर 112 वर्ष पूर्व तक इसमें सौर उर्जा से उत्पादन केवल 3.3 गीगावाट ही था जो कि अब बढ़कर 9.5 गीगावाट हो गया है। तथा अन्य 10 गीगावाट के प्लांट निर्माणाधीन है।

– सतीश कुमार

वर्तमान परिदृश्य

भारत में इस समय कुल मिलाकर 280 गीगावाट बिजली पैदा की जाती है। इससे कोयले के ताप संयंत्र, छोटे–बड़े जल संयंत्र, तेल–डीजल से चलने वाले जनरेटर, न्यूक्लियर व अक्षय, सभी प्रकार के मिलाकर 112 वर्ष पूर्व तक इसमें सौर उर्जा से उत्पादन केवल 3. 3 गीगावाट ही था जो कि अब बढ़कर 9.5 गीगावाट हो गया है। तथा अन्य 10 गीगावाट

के प्लांट निर्माणाधीन है। भारत के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारत में जितनी मात्रा में सौर उर्जा पड़ती है यदि उसका पूरा दोहन कर लिया जाए तो 768 गीगावाट बिजली हम सौर उर्जा से ही प्राप्त कर सकते है यानि सब प्रकार के उत्पादन का भी तीन गुना अकेले सूर्य दे सकता है।

आज हमारा पेट्रोलियम आयात बिल 5.5 लाख करोड़ तक का है। यह भी तब जब तेल की कीमत काफी नीचे है। हमारे कुल आयात का 22–23 प्रतिशत अकेले तेल बिल का है। यदि भारत तेजी से सौर उर्जा अपनाने में सफल हो जाता है तो न केवल हम अपनी तेल आयात बिल बड़ी मात्रा में घटाने में सफल होंगे बल्कि हम बिजली निर्यातर कर आनी आय भी बढ़ा सकते हैं।

अभी हम, न केवल तेजी से उत्पादन करने लगे हैं, बल्कि भारत सरकार अपने की द्वारा निर्धारित लक्ष्य को भी समय से पूर्व प्राप्त करने की स्थिति में आती दिख रही है। 2013 में भारत का लक्ष्य था 2022 तक 23 मेगावाट। मोदी सरकार ने आते ही इसे 2022 तक ही 100 गीगावाट कर दिया और अभी उर्जा मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि हम यह लक्ष्य 2019 तक ही प्राप्त कर लेंगे। यदि ऐसा होता है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा सौर उर्जा उत्पादक देश बन जायेगा।

चुनौतियां

इस सौर उर्जा अभियान की चुनौतियां अनेक है एवं बहुत बड़ी भी है। सबसे पहली चुनौती तो इसके पीवी सेल के भारत में बनने की है। अभी इसका आधार तत्व यानि पॉलिसिलिकॉन, इनगोट, वेफर तो लगभग सारा की आयात करना पड़ता है। फिर उससे बनने वाले पी.वी. सैल उसके मॉड्यूल व पैनल भी 20–25 प्रतिशत ही भारत में बनते है। चीन, ताइवान, जर्मनी व अमरीका से हम सब यह मंगाते है। अपने देश में मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां तो बहुत बन गई है, वे काम भी कर रही है, किंतु वे पैनल, छोटे पार्टस व अन्य सौर चलित समाान ही बना रही है। भारत को यदि सौर उर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तथा आत्मनिर्भर होना है तो उसे पॉलिसिलिकॉन, वाटर हाईगोटस से लेकर पैनल व लाईटस तक का निर्माण भारत में ही करना होगा और वह भी भारतीयों द्वारा।

हमें इसके लिए न केवल भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना होगा, बल्कि यह आधार–इण्डस्ट्रीज होने से सरकार सीधे या पीपीपी आधार पर भी यह कार्य कर सकती है। फिर आवश्यकतानुसार चीन के आयात पर एंटी डंपिंग डयूटी लगाकर, भारतीय इंडस्ट्री को खड़ा भी किया जा सकता है।

आज हमारा पेट्रोलियम आयात बिल 5.5 लाख करोड़ तक का है। यह भी तब जब तेल की कीमत काफी नीचे है। हमारे कुल आयात का 22–23 प्रतिशत अकेले तेल बिल का है।

केंद्र व राज्यों की नीतियां सरल हो, सब्सिडी नीचे तक शीघ्र पहुंचे, ऑन–ग्रिड सिस्टम जल्दी से प्रदेश लागू करें। इस विषय पर भी ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। अभी भारत के 100 गीगावाट के लक्ष्य में 40 गीगावाट रूट टॉप, 20 गीगावाट यूटिलिटी पार्क (मेगावाट तक) व 40 गीगावाट बड़े सोलर पार्क से तय है। किंतु बड़े सोलर पार्क में तो 65–70 प्रतिशत तक की लक्ष्य प्राप्ति प्रतिवर्ष की हो रही है, जबकि छोटे पार्क में 12–13 प्रतिशत व रूट टॉप में तो केवल 8–9 प्रतिशत ही प्रगति है। जबकि रूट टॉप अति महत्व का है। इस हेतु जनजागरण के बड़े प्रयास करने चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच के प्रयास

इस विषय की उपयोगिता व आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने इस विषय में बड़ी पहल की। डॉ. भगवती प्रकाश के नेतृत्व में भारतीय सोलर पावर डेवलपमेंट फोरम (बीएसडीएफ) का गठन हुआ। इस फोरम ने केंद्र सरकार से लेकर सामान्य जनता तक से संवाद शुरू किया है। 'सरकार की नीति भारतीय इंडस्ट्रीज के अनुकूल कैसे बने' इस विषय में ठोस सुझाव दिए है तथा विभिन्न स्तर पर बैठकें, गोष्ठी, सेमिनार करके सारे देश में जनजागरण अभियान छेड़ा है। प्रांत–प्रांत में छोटे–बड़े कार्यक्रम हो रहे है। ऐसा विश्वास है कि भारत सरकार तथा स्वदेशी जागरण मंच के प्रयत्न से एवं अन्य सौर उर्जा प्रेमी व्यक्तियों व संगठनों के प्रयत्नों से भारत शीघ्र ही सौर उर्जा के क्षेत्र में वास्तव में दुनिया का नेतृत्व करने लगेगा। सौर उर्जा अभियान की सफलता भारत में सुनिश्चित है।

सामान्य जानकारी

एक दो कमरे वाले घर में एक किलोवाट यूनिट का सौर पैनल पर्याप्त होता है। इस पर राज्यों की सब्सिड़ी 30 प्रतिशत, घटाकर 60 से 65 हजार रूपये का खर्च आता है जो बिजली दरे अभी है उस हिसाब से 2–2.5 वर्ष में यह खर्चा निकल आता है फिर 20–22 वर्ष तक बिजली मुफ्त मिलती रहेगी क्योंकि अधिकृत पैनल की आयु 22 से 25 वष है एवं इसका सतत लागत कुछ नहीं होती। आजकल राज्यों में ही ऑनग्रीड हो जाने से बैटरी नहीं लगानी पड़ती है व वर्षा अथवा सूर्य न निकलने पर भी बिजली सप्लाई बनी रहती है। किसी प्रकार का विकिरण या अन्य नुकसान नही। हर जिले में सरकार ने अपना नवीन उर्जा विभाग खोला हुआ है। सामान्यता एडीसीओ उसका प्रमुख है। इस प्रकार की विस्तृत जानकारी वहां से ले सकते हैं। ❑❑

गरमाती धरती के खतरे

दुनिया भर के वैज्ञानिक अब यह अनुभव करने लगे हैं कि हम आधुनिक विकास के जिस रास्ते पर चल रहे हैं। वह हमारे विनाश का कारण बन सकता है। इसका यह नतीजा है कि आज हमारे लिए सांस लेने के लिए न तो शुद्ध हवा है और न पीने के लिए साफ पानी बचा है। लेकिन अब खतरा इससे भी बड़ा आने वाला है। भविष्य की तस्वीर बड़ी भयावह है अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो 2030 तक 10 करोड़ लोग सिर्फ गरमाती धरती की वजह से मौत के मुंह में समा जायेंगे। 20 विकासशील देशों की ओर से करवाये गये एक अध्ययन की रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2030 तक अमेरिका और चीन के जीडीपी में 2.1 प्रतिशत जबकि भारत के जीडीपी में पांच प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। धरती के गरमाने से ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। इससे धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है, जो समुद्र के जल स्तर को बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण वायु प्रदूषण, भूख और बीमारी से हर साल पचास लाखों लोगों की मौत हो जाती है। 2030 तक हर साल साठ लाख लोगों की मौत इस वजह होगी। इस दर से अगले 15 साल यानि 2030 तक 9 करोड़ लोग जलवायु परिवर्तन का शिकार होंगे। इनमें से 90 प्रतिशत मौत विकासशील देशों में होगी। यह खतरा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, वनों के कटान और आधुनिक विकास की नई–नई तकनीकों के कारण पैदा हुआ है।

धरती के गरमाने से ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। इससे धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है, जो समुद्र के जल स्तर को बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण वायु प्रदूषण, भूख और बीमारी से हर साल पचास लाखों लोगों की मौत हो जाती है। 2030 तक हर साल साठ लाख लोगों की मौत इस वजह होगी।

– निरंकार सिंह

विकासशील देशों की इस अध्ययन रिपोर्ट में 2010 और 2030 में 184 देशों पर जलवायु परिवर्तन के आर्थिक असर का आंकलन किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल विश्व के जीडीपी में 1.6 फीसद यानि 1200 खरब डॉलर की कमी हो रही है। अगर जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो 2030 तक यह कमी 3.2 प्रतिशत हो जायेगी और 2100 तक यह आंकड़ा 10 प्रतिशत को पार कर जायेगा। जबकि जलवायु परिवर्तन से लड़ते हुए कम कार्बन पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था को खड़ा करने मे विश्व जीडीपी का मात्र आधा फीसदी खर्चा होगा। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर गरीब देशों पर होगा। 2030 तक उनके जीडीपी में 11 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। एक अनुमान के मुताबिक धरती के तापमान में एक डिग्री सेल्सियस बढ़ोत्तरी में कृषि उत्पादन में 10 प्रतिशत की गिरावट आती है। अगर बांग्लादेश का उदाहरण लिया जाए तो उसके खाद्यान्न उत्पादन में 40 लाख टन की कमी आएगी। हर साल पृथ्वी पर जल और खनिजों समेत प्राकृतिक संसाधनों के जबरदस्त दोहन से जंगल साफ हो रहे हैं। पीने योग्य पानी की कमी है। लिहाजा भूकंप, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं।

धरती का तापमान जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, वह इस सदी के अन्त तक प्रलय के नजारे दिखा सकता है। ताजे शोध के नतीजों के अनुसार समुद्र का जल स्तर एक मीटर तक बढ़ सकता है। इससे कई देश और भारत के तटीय नगर डूब जायेंगे। दुनिया इसी सदी

में एक खतरनाक वातावरण परिवर्तन का सामना करने जा रही है। भारत समेत पूरी दुनिया का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जायेगा। पेट्रोलियम पदार्थो का कोई वैकल्पिक ईधन ढूंढने में विफल दुनिया भर की सरकारें इन हालात के लिए जिम्मेदार हैं। पीडब्ल्यूसी के अर्थशास्त्रियों ने अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अब वर्ष 2100 तक वैश्विक औसत तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर तक रखना असंभव हो गया है। इसलिए इसके घातक नतीजे सारी दुनिया को भोगने होंगे। वैज्ञानिकों ने वातावरण परिवर्तन की किसी घातक और अविश्वसनीय स्थिति को टालने के लिए वैकल्पिक तापमान का औसत दो डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य के साथ ही वैज्ञानिकों ने कहा था कि कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन करने वाले इस ईंधन के बदले किसी कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन की तलाश की जाए। पर संयुक्त राष्ट्र के अंतरसरकारी पैनल ने पाया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब काफी देर हो चुकी है। 2 डिग्री सेल्सियस तापमान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को अगले 39 सालों में कमोवेश 5.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पूरी तरह कार्बन रहित बनाना होगा। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से दुनिया ने इस लक्ष्य को कभी छुआ तक नहीं है। इस मसले पर पीडब्ल्यूसी के साझीदार लोओ जानसन का कहना है कि इस सदी के कगार पर वातावरण परिवर्तन से ये दुनिया बदलने वाली है। अगर कार्बन रहित कामकाज की दर को दोगुना भी कर दिया जाए तो भी इस सदी के अंत तक निरन्तर कार्बन उत्सर्जन के कारण 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और बढ़ जायेगा। लेकिन अगर अभी भी 2 डिग्री के लक्ष्य का पचास प्रतिशत प्रयास भी किया जाए तो कार्बन रहित वातावरण में छह स्तरीय सुधार हो सकता है। अब हम किसी खतरनाक परिवर्तन से बचने की कगार को तो पार कर ही चुके हैं। इसलिए हमें एक गर्म दुनिया में खुद को बनाए रखने की योजना बनानी होगी।

इस ग्लोबल वार्मिंग के कहर से सबसे ज्यादा एशियाई देश प्रभावित होंगे। अगले दो सौ सालों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली मानसून प्रणाली बहुत कमजोर पड़ जायेगी। इससे बारिश और जल की अत्यधिक कमी होगी। जबकि कृषि प्रधान देश में आज भी खेती पूरी तरह से मानसून पर ही निर्भर है। साथ ही देश के मौसमों में भी इसमें अमूल–चूल परिवर्तन होने की पूरी आशंका है। एक ताजा शोध में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दो शतकों में बारिश 40 से 70 प्रतिशत तक कम हो जायेगी। इससे मानसूनी बारिश से आने वाला ताजा पानी देशवासियों के लिए कम पड़ेगा। खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी नहीं होगा। इससे देश में जल की ही नहीं, खाद्यान्नों की भी कमी हो जायेगी। भारत में मानसून जून से लेकर सितम्बर तक कमोवेश चार महीने रहता है। ये मौसम देश की एक अरब बीस करोड़ आबादी के लिए पर्याप्त मात्रा में धान, गेहूं और मक्का जैसी उपयोगी फसलें उगाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये सारी प्रमुख फसलें मानसूनी बारिश पर ही निर्भर करती है। दक्षिण–पश्चिम का ये मानसून देश में 70 प्रतिशत बारिश के लिए जिम्मेदार है।

पोस्टडैम इंस्टीट्यूट फार क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च एंड पोस्टडैम यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अपने ताजा शोध में पाया कि मानव जाति 21वीं सदी के अन्त तक पहुंचने की कगार पर है। लेकिन 22वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग की अधिकता के कारण दुनिया का तापमान हद से ज्यादा बढ़ चुका होगा। इनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर नाम की पत्रिका में प्रकाशित इस शोध में बताया गया है कि बसंत ऋतु में प्रशांत क्षेत्र के वाकर सरकुलेशन की आवृत्ति बढ़ सकती है। इसलिए मानसूनी बारिश पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। वाकर सरकुलेशन पश्चिमी हिंद महासागर में अक्सर उच्च दबाव लाता है। लेकिन जब कई सालों में अलनीनो उत्पन्न होता है तब दबाव का ये पैटर्न पूर्व की ओर खिसकता जाता है। इससे भारत के थल क्षेत्र में दबाव आ जाता है और मानसून का इलाके में दमन हो जाता है। ये स्थिति खासकर तब उत्पन्न होती है जब बसंत में मानसून विकसित होना शुरू होता है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार भविष्य में जब तापमान और अधिक बढ़ जायेगा तब वाकर सरकुलेशन औसत रहेगा और दबाव भारत के थल क्षेत्र पर पड़ेगा। इससे अलनीनो भी नहीं बढ़ पायेगा। इससे मानसून प्रणाली विफल हो जायेगी और सामान्य बारिश के मुकाबले भविष्य में 40 से 70 प्रतिशत बारिश ही होगी।

भारतीय मौसम विभाग ने सामान्य बारिश का पैमाना 1870 के शतक के अनुसार बनाया था। मानसूनी बारिश में कमी सब जगह समान रूप से नहीं होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसूनी बारिश कम होने से भी ज्यादा भयावह स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमें एक ऐसी दुनिया में जीने की तैयारी कर लेनी चाहिए जहां सब कुछ हमारे प्रतिकूल होगा। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ऐसे हालात प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और आधुनिक तकनीक के कारण ही पैदा हो रहे हैं इसलिए हम एक महाविनाश की ओर जा रहे हैं जिसकी कल्पना हमारे पुराणों में कलयुग के अन्त के रूप में पहले से ही घोषित की जा चुकी है। ❑❑

आयुर्वेद में अस्थमा का उपचार

अस्थमा एक यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ है– 'जल्दी–जल्दी सांस लेना' या 'सांस लेने के लिए जोर लगाना'। जब किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ता है तो वह सामान्य सांस के लिए भी गहरी–गहरी या लंबी–लंबी सांस लेता है; नाक से ली गई सांस कम पड़ती है तो मुंह खोलकर सांस लेता है।
– स्वदेशी संवाद

अस्थमा (दमा) एक गंभीर एवं एलर्जी से संबंधित बीमारी है, जो श्वास नलिकाओं को प्रभावित करती है। श्वास नलिकाएं फेफड़े से हवा को अंदर–बाहर करती हैं। अस्थमा होने पर इन नलिकाओं की भीतरी दीवार में सूजन होता है। जिसमें आपके फेफड़ों के वायुमार्ग संकीर्ण हो जाता है और बलगम बनता है। यह सूजन नलिकाओं को बेहद संवेदनशील बना देता है और किसी भी बेचैन करने वाली चीज के स्पर्श से यह तीखी प्रतिक्रिया करता है। जब नलिकाएं प्रतिक्रिया करती हैं, तो उनमें संकुचन होता है और उस स्थिति में फेफड़े में हवा की कम मात्रा जाती है। इससे खांसी, नाक बजना, छाती का कड़ा होना, रात और सुबह में सांस लेने में तकलीफ आदि जैसे लक्षण पैदा होते हैं। अस्थमा (दमा) के मरीजों की संख्या दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है।

अस्थमा या दमा एक अथवा एक से अधिक पदार्थों (एलर्जेन) के प्रति शारीरिक प्रणाली की अस्वीकृति (एलर्जी) है। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर की प्रणाली उन विशेष पदार्थों को सहन नहीं कर पाती और जिस रूप में अपनी प्रतिक्रिया या विरोध प्रकट करती है, उसे एलर्जी कहते हैं। हमारी श्वसन प्रणाली जब किन्हीं एलर्जेंस (एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ) के प्रति एलर्जी प्रकट करती है तो वह अस्थमा होता है। यह सांस संबंधी रोगों में सबसे अधिक कष्टदायी है। अस्थमा के रोगी को सांस फूलने या सांस न आने के दौरे बार–बार पड़ते हैं और उन दौरों के बीच वह अकसर पूरी तरह सामान्य भी हो जाता है।

अस्थमा एक यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ है– 'जल्दी–जल्दी सांस लेना' या 'सांस लेने के लिए जोर लगाना'। जब किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ता है तो वह सामान्य सांस के लिए भी गहरी–गहरी या लंबी–लंबी सांस लेता है; नाक से ली गई सांस कम पड़ती है तो मुंह खोलकर सांस लेता है। वास्तव में रोगी को सांस लेने की बजाय सांस बाहर निकालने में ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि फेफड़े के भीतर की छोटी–छोटी वायु नलियां जकड़ जाती हैं और दूषित वायु को बाहर निकालने के लिए उन्हें जितना सिकुड़ना चाहिए उतना वे नहीं सिकुड़ पाती। परिणामस्वरूप रोगी के फेफड़े फूल जाते हैं, क्योंकि रोगी अगली सांस

अस्थमा का दौरा जब तेज होता है तो दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार दोनों बढ़ जाती हैं तथा रोगी बेचैन व थका हुआ महसूस करता है।

भीतर खींचने से पहले खिंची हुई सांस की हवा को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता।

आयुर्वेद में इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, आयुर्वेद पद्धति के प्रयोग से दमे से पीड़ित व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। दमे का दौरा पड़ने से श्वास नलिकाएं पूरी तरह बंद हो सकती हैं, जिससे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को आक्सीजन की आपूर्ति बंद हो सकती है। यह चिकित्सकीय रूप से आपात स्थिति है। दमे के दौरे से मरीज की मौत भी हो सकती है।

अस्थमा के लक्षण

अस्थमा या तो धीरे–धीरे उभरता है अथवा एकाएक भड़कता है। जब अस्थमा एकाएक भड़कता है तो उससे पहले खांसी का दौरा होता है, किंतु जब अस्थमा धीरे–धीरे उभरता है तो उससे पहले आमतौर पर श्वास प्रणाली में संक्रमण हो जाया करता है। अस्थमा का दौरा जब तेज होता है तो दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार दोनों बढ़ जाती हैं तथा रोगी बेचैन व थका हुआ महसूस करता है। उसे खांसी आ सकती है, सीने में जकड़न महसूस हो सकती है, बहुत अधिक पसीना आ सकता है और उलटी भी हो सकती है। दमे के दौरे के समय सीने से आनेवाली आवाज तंग श्वास नलियों के भीतर से हवा बाहर निकलने के कारण आती है। अस्थमा के सभी रोगियों को रात के समय, खासकर सोते हुए, ज्यादा कठिनाई महसूस होती है।

अस्थमा के कारण

अस्थमा कई कारणों से हो सकते हैं। जैसे– मौसम, खाद्य पदार्थ, दवाइयां, इत्र, परफ्यूम जैसी खुशबू, जानवरों से (जानवरों की त्वचा, बाल, पंख या रोयें से), पेड़ और घास के पराग कण, धूलकण, सिगरेट का धुआं, वायु प्रदूषण, ठंडी हवा या मौसमी बदलाव, पेंट या रसोई की तीखी गंध, सुगंधित उत्पाद, मजबूत भावनात्मक मनोभाव (जैसे रोना या लगातार हंसना) और तनाव, एस्पिरीन और अन्य दवाएं, विशेष रसायन या धूल जैसे अवयव तथा कुछ अन्य प्रकार के पदार्थों से हो सकता हैं। कुछ लोग रुई के बारीक रेशे, आटे की धूल, कागज की धूल, कुछ फूलों के पराग, पशुओं के बाल, फफूंद और कॉकरोज जैसे कीड़े के प्रति एलर्जित होते हैं। जिन खाद्य पदार्थों से आमतौर पर एलर्जी होती है उनमें गेहूं, आटा, दूध, चॉकलेट, बींस की फलियां, आलू, सूअर और गाय का मांस इत्यादि शामिल हैं।

कुछ अन्य लोगों के शरीर का रसायन असामान्य होता है, जिसमें उनके शरीर के एंजाइम (किण्वक) या फेफड़ों के भीतर मांसपेशियों की दोषपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है। अनेक बार अस्थमा एलर्जिक और गैर–एलर्जीवाली स्थितियों के मेल से भड़कता है, जिसमें भावनात्मक दबाव, वायु प्रदूषण, विभिन्न संक्रमण और आनुवंशिक कारण शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार, जब माता–पिता दोनों को अस्थमा या परागज ज्वर (Hay Fever) होता है तो ऐसे 75 से 100 प्रतिशत माता–पिता के बच्चों में भी एलर्जी की संभावनाएं पाई जाती हैं।

तंबाकू के धुएं से भरे माहौल में रहने वाले शिशुओं को अस्थमा होने का खतरा होता है। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई महिला तंबाकू के धुएं के बीच रहती है, तो उसके बच्चे को अस्थमा होने का खतरा होता है।

ध्यान योग्य बातें

- यदि आपके घर में पालतू जानवर है तो उसे अपने विस्तर पर या बेडरूम में न आने दें और उनकी सफाई का ध्यान रखें।
- पंखों वाले तकिए का इस्तेमाल न करें।
- घर में या अस्थमा से प्रभावित लोगों के आस–पास धूम्रपान न करें, संभव हो तो धूम्रपान ही करना बंद कर दें क्योंकि अस्थमा से प्रभावित कुछ लोगों को कपडों पर धुएं की महक से ही अटैक आ सकता है।
- मोल्ड की संभावना वाली जगहों जैसे गार्डन या पत्तियों के ढेरों में काम न करें और न ही खेलें।
- दोपहर के वक्त जब परागकणों की संख्या बढ जाती है उस समय यथासंभव हो सके बाहर न जाए।
- अस्थमा से प्रभावित व्यक्ति से किसी तरह का अलग व्यवहार न करें।
- अस्थमा का अटैक आने पर न घबराएं, इससे परेशानी और भी बढ जाएगी।
- धूल से बचें।
- अस्थमा से प्रभावित बच्चों को उनकी उम्र वाले बच्चों के साथ सामान्य गतिविधियों में भाग लेने दें।
- अस्थमा के बारे में अपनी और या अपने बच्चे की जानकारी बढाएं इससे इस बीमारी पर अच्छी तरह से कंट्रोल करने की समझ बढेगी।

- एलर्जी की जांच कराएं इसकी मदद से आप अपने अस्थमा ट्रिगर्स मूल कारण की पहचान कर सकते है।
- झींकते, खांसते समय रुमाल का प्रयोग करें।
- जुकाम या खांसी होने पर लापरवाही न बरतें, जल्द से जल्द उसका उपचार करें।

आयुर्वेद उपचार

- आयुर्वेदिक दवाएं बहुत सुरक्षित हैं और काफी हद तक समस्या का इलाज है। कुछ आम दवाओं कंटकारी अवालेह, अगस्त्याप्रश, चित्रक, कनाकसव का प्रयोग किया जा सकता है।
- रात का खाना हल्का व सोने से एक घंटे पहले लें।
- सुबह या शाम टहलें और योग में मुख्य रूप से 'प्राणायाम' और भावातीत ध्यान करें।
- अधिक व्यायाम से बचे।
- हवादार कमरे में रहें और सोएं। एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों की सीधी हवा से बचें।
- ठंडे और नम स्थानों से दूर रहें।
- धूम्रपान, चबाने वाली तम्बाकू, शराब और कृत्रिम मिठास और ठंडे पेय न लें। जिन्हें इत्र से इलर्जी हैं, वे अगरबत्ती, मच्छर रेपेलेंट्स का प्रयोग न करें।
- दो तिहाई गाजर का रस, एक

तिहाई पालक का रस, एक गिलास रोज पिएं।
- जौं, कुल्थी, बथुआ, द्रम स्तिच्क अदरक, करेला, लहसुन का अस्थमा में नियमित रूप से सेवन किया जा सकता है।
- मूलेठी और अदरक आधा–आधा चम्मच एक कप पानी में लेना बहुत उपयोगी होता है।
- तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।
- जो लोग इस रोग की चपेट में आ चुके हैं, उनके लिए हर ऋतु के प्रारम्भ में एक–एक सप्ताह तक पंचकर्म की नस्य या शिरोविरेचन चिकित्सा इस रोग की रोकथाम में सहायक होती है।
- रात में यदि दमा प्रकुपित हो जाए, तो छाती और पीठ पर गर्म तिल तेल का सेंक करें।
- घर में एक शीशी प्राणधारा की अवश्य रखें। उसमें अजवाइन का सत् होता है, जिसकी भाप दमा के दौरे में राहत देती है।
- एक चौथाई चम्मच सोंठ, छः काली मिर्च, काला नमक एक चौथाई चम्मच, तुलसी की 5 पत्तियों को पानी में उबाल कर पीने से भी दमा में आराम मिलता है।
- एक चौथाई प्याज का रस, शहद एक चम्मच, काली मिर्च 1/8 चम्मच को पानी के साथ लें।
- आयुर्वेद के अनुसार अस्थमा में खान–पान पर विशेष ध्यान देना चाहिएः हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन जैसे मूंग, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन करें।
- लहसुन, अदरक, मेथी, सोया, परवल, लौकी तरोई, टिंडे आदि का प्रयोग भोजन में अधिक से अधिक करें।
- अस्थमा के रोगी के लिए मोटे पिसे आटे की रोटियां, दलिये की खिचड़ी लाभदायक है।
- मुनक्का व खजूर का प्रयोग लाभदायक होता है।
- हमेशा पीने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करें।

उपरोक्त सभी बातों को आपनी दिनचर्या एवं ध्यान में रखते हुए हम अस्थमा (दमा) जैसी गंभीर एवं संक्रमण बीमारी की समस्या से बहुत हद तक निजाद पा सकते है। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

राष्ट्रीय परिषद बैठक, भोपाल (म.प्र.)

21–22 मई 2016

दिनांक 21 मई 2016 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भोपाल स्थित कार्यालय के सभागार में मंच की राष्ट्रीय परिषद बैठक प्रातः 10.00 बजे प्रारंभ हुई। आंचलिक संघर्ष वाहिनी प्रमुख श्री वंदेशंकर सिंह (झारखंड) ने ''आंधी क्या है–तूफान चले'' गीत प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश के सह प्रांत संयोजक श्री अरूषेन्द्र शर्मा ने व्यवस्था संबंधी सूचनाएं प्रदान की। मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा, सह संयोजकगण प्रो. भगवती प्रकाश, श्री सरोज मित्र, प्रो. बी. एम.कुमारस्वामी, डॉ. अश्वनी महाजन, सीए आर. सुन्दरम्, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महामंत्री श्री जितेन्द्र गुप्त, वनवासी कल्याण आश्रम से श्री कृपा प्रसाद सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण भाला ने भारत माता, राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगडी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के संमुख दीप प्रज्ज्वलन करके बैठक का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने बैठक का संचालन करते हुए देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

श्री अरूण ओझा ने कहा कि वर्ष 1999 में इसी ऐतिहासिक शहर भोपाल में मंच की राष्ट्रीय परिषद बैठक हुई थी। इसमें विश्व व्यापार संगठन के संबंध में भारत की भूमिका को लेकर नारा दिया गया था ''मोड़ो–तोड़ो–छोड़ो''। वर्ष 2016 में एक बार फिर यहां बैठक हो रही है। इतने वर्षों में मंच आगे तो बढ़ा है किंतु प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिस तीव्रता से नए–नए आक्रमण हो रहे हैं हम उसी मात्रा में प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पानी पर धारा 144, कहीं जंगलों में आग, कहीं अति वृष्टि दिखाई दे रही है। सरकार की नीतियों में कुछ अंतर तो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ विकास की ललक के कारण देश के संसाधनों की भारी लूट का तंत्र खड़ा हो रहा है। वह हमें कहां ले जायेगा? ''इस प्रकार के विकास'' से किस प्रकार वापस लौटा जाए? इस बारे में हम इस बैठक में विचार करेंगे।

प्रांतों के वृत्त

विभिन्न कार्यकर्ताओं ने अपने–अपने प्रांतों का विस्तृत वृत प्रस्तुत किया।

कार्य विभाग योजनाएं

निम्नलिखित कार्यकर्ताओं ने प्रस्तुत की– 1. संपर्क विभाग–श्री लालजी भाई पटेल (अ.भा.संपर्क प्रमुख), 2. संघर्ष वाहिनी–श्री अन्नदा शंकर पाणीग्रही (अ.भा. संघर्ष वाहिनी प्रमुख), 3. कोष–श्री संजीव महेश्वरी सी.ए. (अ.भा. सह कोष प्रमुख), 4. प्रचार विभाग–डॉ. निरंजन सिंह (अ.भा. सह प्रचार प्रमुख)।

प्रस्ताव–1

ई–कॉमॅर्स और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों एवं खाद्य मार्केटिंग में विदेशी निवेश वापिस हो!

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद सरकार द्वारा ई–कॉमर्स और खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्य वस्तुओं के विपणन में विदेशी निवेश को अनुमति के लिए क्षोभ एवं विरोध प्रकट करती है। ज्ञात हो कि ई–कॉमर्स में कई विदेशी कंपनियां लंबे समय से गैर कानूनी रूप से कार्यरत है।

स्वदेशी जागरण मंच सरकार को निरंतर चेतावनी देता रहा है कि विदेशी ई–कॉमर्स कंपनियां और विदेशी पूंजी प्राप्त पूर्व में भारत में निर्मित कंपनियां अपनी आर्थिक शक्ति का दुरूपयोग करते हुए, हिंसक कीमत नीति के माध्यम से (देश से थोक और खुदरा दोनों प्रकार के) छोटे–बडे व्यापारियों, पुस्तक विक्रेंताओं, दवा विक्रेताओं और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करने का काम कर रही हैं। ई–कॉमर्स में विदेशी निवेश कानूनी रूप से प्रतिबंधित रहा है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर ई–कॉमर्स कंपनियों को कार्य करने दिया जा रहा है। यह कहा गया है कि विदेशी कंपनियां वास्तव में ई–कॉमर्स कर ही नहीं रही हैं, वे तो केवल 'मार्केट प्लेटफार्म' उपलब्ध करा रही हैं और विक्रेताओं को अपनी वेबसाइटों के माध्यम से सामान बेचने का अवसर दे रही हैं।

स्वदेशी जागरण मंच ने हमेशा से ही कहा है कि चूंकि यह कंपनियां अपनी आर्थिक शक्ति के बलबूते, भारी छूट (डिस्काउंट) देती हैं और कई मामलों में स्टॉक भी करती हैं, इसलिए यह कहना कि ये कंपनियों ई–कॉर्मस नहीं करती हैं, वास्तव में सही नहीं हैं। गैर कानूनी रूप से काम करने वाली ई–कॉमर्स कंपनियां टैक्स चोरी भी करती रही हैं, जिसके संबंध में कई मामलों में जांच भी चल रही हैं। इस बारे में सरकार से अपेक्षा थी कि वह इनको प्रतिबंधित करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने अब इन विदेशी कंपनियों को मान्यता देते हुए ई–कॉमर्स में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान कर दी है। यानि कानून तोडने वालों को पुरस्कृत किया गया है, यह उचित नहीं है।

हालांकि सरकार का कहना है कि ई–कॉमर्स में विदेशी निवेश को अनुमति केवल 'मार्क्रेट प्लेटफॉर्म' मॉडल के लिए है और कंपनियों को छूट देकर कीमतों को प्रभावित करने के लिए रोक लगाई गई है। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच का यह मानना है कि इस संबंध में विदेशी कंपनियों के लिए ई–कॉमर्स कंपनियों को नियंत्रित करने के प्रावधान नहीं हैं।

सर्वविदित है कि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के प्रयास से खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के विरोध में एक राष्ट्रीय आंदोलन खडा हुआ और उसके चलते धोखे से संसद में कानून पारित होने के बावजूद कोई बड़ा विदेशी निवेश खुदरा क्षेत्र में नहीं हो पाया। स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद यह स्मरण करवाना चाहती है कि वर्तमान में केन्द्र में एन.डी.ए. सरकार नेतृत्व कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया था और अपने चुनाव खोषणा पत्र में भी यह वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद विदेशी निवेश को अनुमति देने वाले कानून को बदला जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि कानून को तो बदला नहीं गया, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) में विदेशी निवेश आकृष्ट करने के नाम पर खाद्य प्रसंस्करण और देश में उत्पादित खाद्य पदार्थों के विपणन में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान कर दी है।

सरकार का यह कदम न केवल लघु–कुटीर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए घातक सिद्ध होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निर्माण के महत्वपूर्ण अवसर को भी गंवा देगा। वास्तव में यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहती है तो उसके लिए ग्रामीण स्तर पर विकेन्द्रित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने होंगे और गांवों में ही रोजगार का निर्माण करना होगा। यही नहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और खाद्य मार्केटिंग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति, खाद्य पदार्थों में एकाधिकार को बढ़ावा देगा।

स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय परिषद मांग करती है देश में छोटे व्यापारियों, लघु उद्योगों और किसानों के हितों के संरक्षण हेतु सरकार ई–कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण अैर मार्केटिंग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति देने वाले अपने निर्णयों को वापिस ले। स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय परिषद सरकार को चेतावनी देती है कि वह इस प्रकार के निर्णयों से बचे। राष्ट्रीय परिषद अपने सभी सहयोगी संगठनों सहित सभी कार्यकर्ताओं का आवाह्न करती है कि सरकार के इन निर्णयों के विरोध में व्यापक जन जागरण करें।❑

प्रस्ताव–2

सस्ती दवाओं व चिकित्सा सेवाओं से चिकित्सा की सर्व सुलभता आवश्यक

देश में जीवन शैली जन्य रोगों सहित विविध रोग अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। सभी प्रकार के रोगों के सकल वैश्विक रोग भार (World's disease burden) का 21 प्रतिशत भारत पर है। लेकिन, देश में चिकित्सा सेवाओं की अपर्याप्तता और चिकित्सा सुविधाओं के महंगा होने कारण बड़ी संख्या में लोगों को चिकित्सा सुलभ नहीं हो पा रही है। देश में रोकथाम योग्य रोगों (Preventable illness) व उनसे होने वाली असामयिक मृत्यु की बढ़ती घटनाओं के कारण ही प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की क्षति हो रही है, जिसका मूल्य 9–10 लाख करोड़ रूपये वार्षिक से भी अधिक है। वस्तुतः चिकित्सा पर सार्वजनिक व्यय आज हमारे घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से कम है। यह विश्व के अन्य प्रमुख देशों की तुलना में सबसे 5 प्रतिशत के वैश्विक माध्य Global Median से अत्यन्त कम है। इसलिये बड़ी संख्या में रोगियों व उनके परिजनों को ही चिकित्सा लागत का बड़ा भाग वहन करना पड़ता है। परिणामतः विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज देश में ऊँची चिकित्सा लागतों के कारण प्रतिवर्ष 2.2 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे जा रहे हैं एवं बड़ी संख्या में परिवार ऋणग्रस्त होते जा रहे हैं।

देश की जन–स्वास्थ्य सांख्यिकी के अनुसार आज देश में जीवन शैली जन्य रोग यथा उच्च रक्त चाप, हृदयावरोध, श्वास रोग, मस्तिष्कगत रक्तस्राव जन्य पक्षाघात, मलाशय का कैंसर, मधुमेह, गठिया, मोटापा, निद्रानाश, स्मृतिनाश, स्वलीनता, नशावृत्ति आदि अनेक रोग व मनोविकार तेजी से बढ़े हैं। देश में प्रतिवर्ष 58 लाख लोगों की मृत्यु हृदय व फेफड़े के रोगों, टाइप 2 के मधुमेह व कैंसर जैसे असंक्रामक रोगों से हो रही हैं, जिनकी रोकथाम संभव है। देश आज विश्व की हृदय रोग, मधुमेह, गठिया आदि की राजधानी कहलाने लगा है। आज देश में 6.13 करोड़ मधुमेह के रोगी है और 11.1 प्रतिशत पुरूषों व 10.8 प्रतिशत महिलाओं में रक्त शर्करा (ब्लड शूगर) अत्यंत बढ़ी हुयी है। भारत में उच्च रक्त शर्करा वाले लोगों का यह अनुपात पड़ौसी देशों श्रीलंका, बांग्लादेश व नेपाल आदि से भी उच्च है। हृदय रोग तो आज देश में महामारी की सीमा तक बढ़ता जा रहा है।

देश की अधिकांश चिकित्सा सुविधायें, चिकित्सकों की उपलब्धता एवं विशेषज्ञों की सुलभता आदि बड़े नगरों में ही केन्द्रित हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं का भी सुचारू संचालन नहीं होने से देश के अधिकांश क्षेत्रों में प्रभावी चिकित्सा की यथेष्ट सुलभता नहीं है। इसलिये नगरीय क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र के 63 प्रतिशत लोगों को चिकित्सा हेतु निजी क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 53 प्रतिशत लोग सार्वजनिक क्षेत्र की चिकित्सा सेवाओं से असन्तोष के कारण निजी क्षेत्र की सेवाओं का उपयोग करने को बाध्य होते हैं। विगत दस वर्षों में औसत चिकित्सालयीन व्यय (average hospitalization costs) लगभग 3 गुनी हुयी है। यह प्रचलित मुद्रास्फीति से कहीं अधिक है।

चिकित्सा लागत में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण, आवश्यक दवाओं में कीमत नियंत्रण का अभाव है। पिछली सरकार के शासनकाल में आवश्यक दवाओं की कीमतों में नियंत्रण को निष्प्रभावी बना दिया गया था। स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय परिषद सरकार से मांग करती है कि आवश्यक दवाओं में लागत आधारित की कीमत नीति को बिना देरी लागू करे। एक ओर सरकारी खर्च में कमी से स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण के कारण चिकित्सा लागत बढ़ी है, तो दूसरी ओर सरकारी नीतियों पर विदेशी कंपनियों के प्रभाव के कारण, अनावश्यक टीकाकरण को बढ़ावा मिला है, जिससे आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं में कटौती हो रही है।

देश में प्रति हजार जनसंख्या पर सार्वजनिक क्षेत्र में 1 शैय्या की उपलब्धता भी नहीं है। श्रीलंका में प्रति हजार जनसंख्या पर सार्वजनिक क्षेत्र में 3.1 चिकित्सालय शायिकायें (hospital beds) हैं, चीन में 3, थाईलैण्ड में 2.2, ब्राजील में 2.4, अमेरिका में 3.1 इंग्लैण्ड में 3.9 है। भारत में यह मात्र 0.95 है जो विश्व के प्रमुख देशों में न्यूनतम है। इस संबंध में विश्व औसत 2.9 है। देश में प्रति दस हजार जनसंख्या पर 7 ऐलोपेथी चिकित्सक ही उपलब्ध है। कुछ राज्यों में तो प्रति चिकित्सक रोगी अनुपात 27 से 28 हजार तक आता है। यथा महाराष्ट्र में प्रति चिकित्सक रोगी अनुपात 27,790 व बिहार में 28,391 है। देश में पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों का भी व्यापक चलन है। इसलिये प्रभावी स्वास्थ्य व चिकित्सा व्यवस्था की दृष्टि से सभी चिकित्सा प्रणालियाँ का समेकित व समन्वित विकास आवश्यक है।

वर्ष 2005 में पेटेंट कानून में परिवर्तन से अब 1995 के बाद की आविष्कृत औषधियाँ उत्पाद पैटेंट प्रावधानों के कारण अत्यंत महंगी होती जा रही है। हमारे पेटेंट कानून का पुनः मानवोचित सिद्धान्तों के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिये। महंगी दवाओं के उत्पादन हेतु स्वतः अनिवार्य अनुज्ञापन के प्रावधान किये जाने चाहिये। साथ ही जेनेरिक औषधियों को

प्रोत्साहन, उनके प्रभावी मूल्य नियंत्रण व उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित परीक्षण की आवश्यक है। वर्ष 2004 तक उत्पाद पेटेंट के स्थान पर प्रक्रिया पेटेंट के प्रावधान होने से ही देश विश्व की फार्मेसी कहलाता है।

स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि चिकित्सा के मद पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के साथ–साथ चिकित्सा सेवाओं का दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार किया जाना एवं उनका वहाँ सुचारू संचालन आवश्यक है। महिला स्वास्थ्य, शिशु व जननी स्वास्थ्य व वरिष्ठजनों सहित सभी वर्गों को सब प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएँ न्यायपूर्वक एवं सहजता से उनके निकटतम स्थान पर सुलभ होनी चाहिये। साथ ही देश में सभी प्रकार के चिकित्सा उपकरण, विविध प्रत्यारोपित की जाने वाली चिकित्सा सामग्रियों व उपभोग में आने वाली सामग्रियों के मूल्य बहुत ऊँचे हैं। चिकित्सा हेतु उनके भारी व विभेदकारी मूल्य और जाँचों की ऊँची लागतें भी नियंत्रित की जानी आवश्यक हैं। मंच सरकार से आग्रह करता है कि सभी प्रणालियों की औषधियों के प्रमापीकरण, गुणवत्ता परीक्षण मूल्य नियंत्रण एवं सर्वसुलभता के लिये उचित वैधानिक, नीतिगत, प्रक्रियागत एवं नियामक व्यवस्थागत सुधार व उनमें पारदर्शिता लानी आवश्यक है।

समर्थ, सक्षम व समृद्ध भारत के निर्माण हेतु सभी नागरिकों का निरामय होना आवश्यक है। इस हेतु जहाँ एक ओर प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्यप्रद आहार–विहार व जीवन शैली अपनाने पर ध्यान देना चाहिये वहीं आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक नागरिक को समुचित उपचार सहजता से निःशुल्क व न्यायपूर्वक या उसके द्वारा वहन करने योग्य शुल्क पर सुलभ होना चाहिये। ❑

पारित प्रस्ताव

1. ई–कॉमर्स व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश वापिस हो– डॉ. अश्वनी महाजन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा ने इसका समर्थन किया।

प्रस्ताव की भूमिका रखते हुए डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि इस विषय पर यू.पी.ए. सरकार के समय स्वदेशी जागरण मंच सहित अनेक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने घोषित रूप से पूरा समर्थन किया था एवं अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया। किंतु सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार इसे "**चोर दरवाजे**" से ला रही है। इससे भारी बेरोजगारी बढ़ेगी तथा व्यापार पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हो जायेगा।

2. सस्ती दवाओं व चिकित्सा सेवाओं से चिकित्सा की सर्वसुलभता आवश्यक– डॉ. भगवती प्रकाश ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं डॉ. बी.एल. जागेटिया (प्रांत सहसंयोजक, राजस्थान), प्रो. राजकुमार मित्तल (उत्तर क्षेत्र सह विचार मंडल प्रमुख) एवं श्री अमोल पुसद्कर (प्रांत संयोजक, महाराष्ट्र) ने इसका समर्थन किया।

प्रस्ताव की भूमिका रखते हुए डॉ. भगवती प्रकाश ने कहा कि शहरी क्षेत्र की 70 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र की 63 प्रतिशत जनसंख्या प्राईवेट अस्पतालों में ईलाज करवाने के लिए मजबूर है। चिकित्सा अत्यंत मंहगी होती जा रही है जिसके कारण लोगों को या तो अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है या फिर भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। जिसके कारण प्रतिवर्ष कुल जनसंख्या के 2.2 प्रतिशत (2 करोड़ 70 लाख) लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। अतः इलाज सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए।

3. विकासः अस्तित्व के लिए – प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी ने इसका वाचन किया। श्री अरूण ओझा ने समर्थन किया।

प्रस्ताव की भूमिका रखते हुए प्रो. बी.एम. कुमारस्वामी ने कहा कि विकास का पश्चिमी मॉडल लालच पर आधारित है। इसमें मनुष्य–जीव–वनस्पति–पर्यावरण रक्षा–जल–जमीन–जंगल आदि के बीच में कोई सामंजस्य ही नहीं दिखाई देता। विकास के नाम पर संसाधनों की लूट के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। जिसके कारण मानवता का अस्तित्व ही संकट में पड़ रहा है।

प्रस्तावों की प्रति संलग्न है।

विशेष व्याख्यान

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के विषय पर प्रो. भगवती प्रकाश, स्वदेशी एजेंडा के विषय पर श्री योगानंद काले (पूर्व राष्ट्रीय सहसंयोजक), आई.पी.आर. के विषय पर श्री कश्मीरी लाल एवं श्री

राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय परिषद सदस्य

प्रस्ताव–3

विकास के लिए अस्तित्व दांव पर नहीं

ग्लोबल वार्मिंग अब केवल राष्ट्रीय और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में जानकारी बढ़ाने के लिए चर्चा का विषय नहीं रह गया। अब खतरा हमारे दरवाजे पर है। भारत में ऐतिहासिक रूप से तापमान में वृद्धि हो रही है, जो पिछले 100 सालों में नहीं देखी गई है। इस साल अप्रैल और मई महीने में देश के विभिन्न भागों में अलग–अलग न्यूनतम 40 डिग्री सेंटिग्रेड और अधिकतम 50 डिग्री सेंटिग्रेड तक आंका गया।

चिलचिलाती धूप और बिलबिलाती गर्मी में पीने के पानी का संकट कई तरीके की बीमारियां का कारण बन रहा है। इस बेहताशा गर्मी का एक ओर पहलू यह है कि इससे खेती में खड़ी फसलें भी बर्बाद हो रही है जिससे किसान ओर दयनीय स्थिति में पहुंच रहे है। चिंता की एक बात और यह है कि जंगलों में भंयकर आग फैल रही है और पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार उत्तराखंड में 6000 एकड़ जंगल क्षेत्र आग की भेंट चढ़ गया है।

इस साल भारत में ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बुरा असर है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन पर हो रहे सम्मेलन पिछले दशक में हुए सम्मेलनों से ज्यादा गंभीर है। हमें आने वाले दिनों में प्रकृति के इस बदलाव के प्रति और गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

जीवन के प्रति इस खतरे को देखते हुए स्वदेशी जागरण मंच सरकार से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ओर गंभीर प्रयास करने की मांग करता है। स्वदेशी जागरण मंच की मांग है कि –

1. जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जलाश्यों और अन्य जल स्रोतों का पूरी तरह कायाकल्प किया जाए।
2. कोका–कोला, पेप्सी–कोला और अन्य पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों पर या तो अंकुश लगाया जाए या उन्हें बंद किया जाए, क्यूंकि ये सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी करती है।
3. वर्षा जल संग्रह से संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए और लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित किया जाए।
4. विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए और इनका संरक्षण किया जाए। इसके अलावा नये जंगलों को बनाने और उसमें विभिन्न किस्म के पेड़ लगाने को प्राथमिकता दी जाए।
5. अधिक जल उपयोग वाली फसलों जैसे गन्ना इत्यादि की खेती जल भराव वाले क्षेत्रों में की जाए और कम सिंचित क्षेत्र में कम पानी के उपयोग वाली फसल उगाई जाए।
6. सरकार यह ध्यान में रखे कि विकास से कहीं अधिक महत्व अस्तित्व को बचाए रखने में है।
7. आपदा राहत एजेंसियों की संख्या ओर बढ़ाई जाए और इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए ताकि बाढ़ या आगजनी की स्थिति में लोगों तक तत्काल राहत पहुंच सके।

मंच आमजन और अपने कार्यकर्ताओं से यह अपील करता है कि वह जल संरक्षण से जुड़े सभी सरकारी एवं निजी कार्यक्रमों में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले। पानी का दुरूपयोग रोके, जंगलों का संरक्षण करें और पौधा रोपण अभियान चलाये। क्योंकि हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत जरूरी कदम है। ❑

भगवती प्रकाश, जी.एम. फसलों के विषय पर डॉ. अश्वनी महाजन, मुक्त व्यापार समझौते के विषय पर श्री आर. सुन्दरम, सौर उर्जा के विषय पर श्री सतीश कुमार, स्वदेशी परंपराएं एवं खेल के विषय पर श्रीमति राजलक्ष्मी ने विस्तार से विषय रखा।

राष्ट्रीय विचार वर्ग

◆ *पूर्वी क्षेत्र*– 13,14,15 अगस्त 2016, बलांगीर (उड़ीसा), प्रतिभागी संख्याः बिहार–30, झारखंड–40, उड़ीसा–70, असम–5, सिक्किम–5, अरूणाचल प्रदेश–2, कुल संख्या–152 प्रतिनिधि।

◆ *पश्चिमी क्षेत्र*– 22,23,24 जुलाई 2016, इंदौर (म.प्र.)। प्रतिभागी संख्याः महाराष्ट्र–20, गुजरात–22, म.प्र.–75, छत्तीसगढ़–15, कुल संख्या–132 प्रतिनिधि।

◆ *उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड क्षेत्रः* 24,25,26 जून 2016, इलाहाबाद (उ.प्र.)। प्रतिभागी संख्याः प.उ.प्र.–40, अवध–30, काशी–70, उत्तराखंड–5, कुल संख्या–145 प्रतिनिधि।

◆ *उत्तर क्षेत्र*–10,11,12 जून 2016, पलवल (हरियाणा)। प्रतिभागी संख्याः जम्मू कश्मीर–5, हि.प्र.–25, पंजाब–25, हरियाणा–60, दिल्ली–75, राजस्थान–50, कुल संख्या–240 प्रतिनिधि।

◆ *दक्षिण क्षेत्र*– तिथियों की सूचना शीघ्र भेजी जायेगी।

विचार वर्ग का प्रतिनिधि शुल्क रू. 250/– है।

राष्ट्रीय सभा

12,13,14 नवंबर 2016, गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, कुरूक्षेत्र

(हरियाणा)। दिनांक 11 नवंबर को दोपहर 3.00 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक इसी स्थान पर होगी। प्रतिभागी संख्याः केरल–10, तमिलनाडू–30, कनार्टक–34, तेलंगाना–20, आंध्र प्रदेश–20, महाराष्ट्र–20, गुजरात–30, महाकौशल (म.प्र.)–45, मालवा (म.प्र.)–30, मध्य भारत–35, छत्तीसगढ़–20, राजस्थान–60, जम्मू कश्मीर–10, हि. प्र.–80, पंजाब–25, हरियाणा–80, दिल्ली–90, प.उ.प्र.–45, अवध–50, काशी–70, उत्तराखंड–30, बिहार–65, झारखंड–50, उडीसा–60, बंगाल–25, उत्तर पूर्व राज्य–10, कुल संख्या–853 पुरूष व 192 महिलाएं (1045 प्रतिनिधि)।

प्रतिनिधि शुल्क– रू.300/– प्रति व्यक्ति।

पात्रताः राष्ट्रीय सभा में प्रांतीय परिषद के सदस्य एवं इससे उपर के स्तर के कार्यकर्ता अपेक्षित है। प्रांतीय परिषद से तात्पर्य यह है कि सभी नगर, जिला, विभाग एवं ऊपर स्तर के संयोजक/सह संयोजक/संगठक तथा समविचारी संगठनों के 2–2 प्रतिनिधि। सभी प्रांत अपने जिले/प्रांत का बैनर झंडे साथ लेकर आएं।

संगठनात्मक

श्री कश्मीरी लाल ने विभिन्न प्रांतों में संगठनात्मक ढांचा सुदृढ़ करने के सुझाव दिये। देशी विदेशी वस्तुओं की सूची, अधिकाधिक सदस्य बनाने, जिला/प्रांत विचार वर्ग आदि के विषय में चर्चा की।

अन्य

बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के प्रथम राष्ट्रीय संगठक एवं राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगडी के अनन्य सहयोगी श्री रामदास पांडे (भारतीय मजदूर संघ), मध्य प्रदेश से पूर्व राज्यसभा सांसद श्री रघुनन्दन शर्मा, भारतीय मजदूर संघ (म.प्र.) के पूर्व प्रदेश महामंत्री श्री सुल्तान सिंह का परिचय श्री अरूण ओझा ने कराया। मध्य प्रदेश स्वदेशी जागरण मंच की ईकाई ने स्मारिका का विमोचन किया एवं मंचासीन सभी प्रतिनिधियों को स्मृति चिह्न भेंट किया। श्री अरूण ओझा ने व्यवस्था के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन किया।

स्मारिका विमोचन

नई नियुक्तियां

निम्नलिखित कार्यकर्ताओं को नए दायित्व प्रदान किए –

◆ क्षेत्रीय दायित्व– श्री रमेश दवे (गुजरात, महाराष्ट्र प्रांतों के सह क्षेत्र संयोजक),

◆ प्रांतीय दायित्व – 1.गुजरात–श्री धीरेन्द्र भाई जेठवा (प्रांत संयोजक), श्री हसमुख भाई ठाकर (प्रांत सहसंयोजक), श्री अश्विन भाई सोनी (प्रांत सहसंयोजक)

2. तमिलनाडू– श्रीमति राजलक्ष्मी (प्रांत सहसंयोजक),

3. कर्नाटक– श्री विजय कृष्ण (प्रांत सहविचार मंडल प्रमुख),

◆ राष्ट्रीय परिषद सदस्य – श्री नीलेश भाई परमार (गुजरात), श्री प्रभास पाणीग्रही (उड़ीसा)

आगामी कार्यक्रम/योजनाएं

1. ***बारहवीं राष्ट्रीय सभा*** – 12,13,14 नवंबर 2016, कुरूक्षेत्र (हरियाणा), दिनांक 11 नवंबर को दोपहर 3.00 बजे इसी स्थान पर रा.प. बैठक होगी।

2. ***केंद्रीय कार्यसमिति बैठक*** – 3,4 सितंबर 2016, नई दिल्ली

3. **राष्ट्रीय विचार वर्ग** – पत्रक में तिथियां व स्थान का उल्लेख किया गया है।

4. **बुद्धिजीवी सम्मेलन**– दिल्ली के प्रतिष्ठित Delhi School of Economics एवं JNU सहित देश के 55 विश्वविद्यालयों में एक वर्ष में मंच के कार्यक्रम हुए हैं। इनमें से बुद्धिजीवियों को चिन्हित करके उनके नाम/पता दिल्ली में प्रो. राजकुमार मित्तल (उत्तर क्षेत्र सह विचार मंडल प्रमुख) को ईमेल (dr123mittal@yahoo.com)/फोन (08586888937) पर शीघ्र भेजें। जुलाई माह में ऐसे बुद्धिजीवियों का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जायेगा।

5. **संघर्ष वाहिनी बैठक** – दिनांक 27,28 अगस्त 2016, तुलसी भवन, बिष्टुपुर, जमशेदपुर (झारखंड), यह बैठक दिनांक 27 अगस्त को प्रातः 10 बजे प्रारंभ होकर 28 अगस्त की दोपहर 1.00 बजे तक चलेगी। इसमें सभी जिला/विभाग/नगर/प्रांत के संघर्ष वाहिनी प्रमुख अपेक्षित है। ऐसे कार्यकर्ता जिनको भविष्य में दायित्व दिया जा सकता है, वे भी अपेक्षित है। शुल्क–100 रू. प्रति व्यक्ति, संपर्क सूत्र– श्री बंदेशकर सिंह–आंचलिक संघर्ष वाहिनी प्रमुख (09431179660, 08987517941, bandejsr@gmail.com)।

6. चीन विरोधी अभियान– दीपावली से पूर्व एक सप्ताह तक चीनी वस्तुओं के विरोध में जन जागरण। रक्षा बंधन के अवसर पर भी जन जागरण करना है। जिलाधिकारियों को ज्ञापन भी देना है।

7. परिवार सम्मेलन– प्रखंड/नगर/जिला/विभाग/प्रांत स्तर की सभी ईकाईयो ने परिवार सम्मेलन आयोजित करने है।

8. स्वदेशी सप्ताह– 25 सिंतबर से 2 अक्टूबर तक स्वदेशी सप्ताह मनाना है। इससे पूर्व जिला/प्रखड/नगर/ विभाग/प्रांत की ईकाईयों ने शिक्षक सम्मेलन करने हैं। इसका स्वाभाविक लाभ स्वदेशी सप्ताह की गतिविधियों में प्राप्त होगा। (स्वदेशीः क्या–क्यूं, कैसा को कार्यक्रमों का आधार बनाएं।)

9. नई इकाईयों का गठन– प्रत्येक स्तर की ईकाई ने प्रयासपूर्वक नई इकाईयां खड़ी करनी है।

10. एफ.डी.आई. के मुद्दे पर सभी वर्गों में जन जागरण। यह संभव है कि राष्ट्रीय सभा में इस पर कोई देश व्यापी अभियान/जनमत संग्रह का निर्णय लिया जाए। अतः जन जागरण का कार्य पूरा करके ही राष्ट्रीय सभा में आएं। इस हेतु पदयात्राएं/पत्रक वितरण/मोटरसाईकल यात्रा व अन्य कार्यक्रम करें।

11. सौर उर्जा के विषय पर सभी प्रांतों ने कार्यक्रम करने हैं।

12. कृषि के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कार्यक्रम करने है।

13. बाबू गेनू बलिदान दिवस (इस अवसर पर दैनन्दिन जीवन में स्वदेशी को आधार बनाकर कार्यक्रम करने है।)

14. आई.पी.आर. से जुड़े योग्य बुद्धिजीवियों को चिन्हित करके उनकी जानकारी श्री सतीश कुमार को देनी है।

समारोप

श्री अरूण ओझा ने कहा कि दिनांक 2,3,4 सितंबर 1993 को मंच का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस समय ठेंगडी जी ने कहा था कि स्वदेशी जागरण मंच का अपना कोई संगठन नहीं है। यह विभिन्न संगठनों का साझा मंच है। आज देखने में आ रहा है कि स्वदेशी जागरण मंच का अपना संगठन बढ़ रहा है। देश के अधिकांश जिलों से 1040 संयोजक/सहसंयोजक/संगठक स्तर के कार्यकर्ता कुरूक्षेत्र सभा में आ रहे हैं। किंतु हम संतुष्ट नहीं है। क्योंकि समस्याएं भी रोग–अपसंस्कृति–बेरोजगारी के रूप में बढ़ रही हैं। अतः सभी कार्यकर्ताओं को अपनी क्षमता शीघ्रता से बढ़ानी होगी। हम सभी दिए गए कार्यक्रमों पर पूरी शक्ति से काम करते हुए कुरूक्षेत्र की राष्ट्रीय सभा में पुनः एकत्रित होंगे। इसी आह्वान के साथ राष्ट्रीय परिषद बैठक संपन्न हो गई। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

संचार क्रांति के साथ लोगों के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गये हैं। मोबाईल तो जैसे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो गया हो। हर प्रकार के संदेशों के आदान–प्रदान के लिए मोबाईल एक वरदान यंत्र हो गया है। मोबाईल का ही एक प्रमुख फीचर है–व्हाटसएप। इस एप के जरिये 24 घंटे लोग एक–दूसरे से जुड़े रहते है। कुछ तो बातें काम की होती है तो कुछ बेकाम की। यहां हम व्हाटसएप के जरिये हस्तांतरित कुछ संदेशों को उपयोगिता के आधार पर यहां प्रस्तुत कर रहे हैं –

चीनी एक जहर

- चीनी बनाने की प्रक्रिया में गंधक का सबसे अधिक प्रयोग होता है। गंधक यानि पटाखों का मसाला।
- गंधक अत्यंत कठोर धातु है जो शरीर में चला तो जाता है परंतु बाहर नहीं निकलता ।
- चीनी कॉलेस्ट्रॉल बढ़ाती है जिसके कारण हृदयघात या हार्ट अटैक आता है।
- चीनी शरीर के वजन को अनियंत्रित कर देती है जिसके कारण मोटापा होता है ।
- चीनी रक्तचाप या ब्लड प्रैशर को बढ़ाती है।
- चीनी ब्रेन अटैक का एक प्रमुख कारण है।
- चीनी की मिठास को आधुनिक चिकित्सा में सूक्रोज़ कहते हैं, जो इंसान और जानवर दोनों पचा नहीं पाते।
- चीनी बनाने की प्रक्रिया में 23 हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जाता है।
- चीनी डाइबिटीज़ का एक प्रमुख कारण है।
- चीनी पेट की जलन का एक प्रमुख कारण है ।
- चीनी शरीर मे ट्राइ ग्लिसराइड को बढ़ाती है ।
- चीनी पेरेलिसिस अटैक या लकवा होने का एक प्रमुख कारण है।
- चीनी बनाने की सबसे पहली मिल अंग्रेजों ने 1868 में लगाई थी ।
- उसके पहले भारतवासी शुद्ध देशी गुड़ खाते थे और कभी बीमार नहीं पड़ते थे ।
- जितना हो सके, चीनी से गुड़ पर आएं। ❑

ॐ की महत्ता

ऊँ (ओउम्) तीन अक्षरों से बना है। 'अ' 'उ' एवं म्। "अ" का अर्थ है उत्पन्न होना, "उ" का तात्पर्य है उठना, उड़ना अर्थात् विकास, "म" का मतलब है मौन हो जाना अर्थात् "ब्रह्मलीन" हो जाना।

ऊँ संपूर्ण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का द्योतक है। ऊँ का उच्चारण शारीरिक लाभ प्रदान करता है।

ऊँ और थायरॉयडः– ऊँ का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होती है जो थायरायड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

ऊँ और घबराहटः–अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ऊँ के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं।

ऊँ और तनावः– यह शरीर के विषैले तत्त्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण करता है।

ऊँ और खून का प्रवाहः– यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है।

ऊँ और पाचनः– ऊँ के उच्चारण से पाचन शक्ति तेज़ होती है।

ऊँ लाए स्फूर्तिः– इससे शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है।

ऊँ और थकानः– थकान से बचाने के लिए इससे उत्तम उपाय कुछ और नहीं।

ऊँ और नींदः– नींद न आने की समस्या इससे कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको करने से निश्चित नींद आएगी।

ऊँ और फेफड़ेः– कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों में मज़बूती आती है।

ऊँ और रीढ़ की हड्डीः– ऊँ के पहले शब्द का उच्चारण करने से कंपन पैदा होती है। इन कंपन से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और इसकी क्षमता बढ़ जाती है।

ऊँ दूर करे तनावः– ऊँ का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव–रहित हो जाता है।

प्रतिरोधक क्षमता बढना–ऊँ के उच्चारण से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (बिमारियों से लड़ने की क्षमता) बढ़ती है।

उपरोक्त गुणों को देखते हुए कुछ समय जरुर ऊँ का उच्चारण करें और आपने मित्रों, बच्चों एवं सगे–संबंधियों को इसके लिए प्रेरित करें। ❑❑

एनएसजी में भारत की एंट्री रोकने में लगा पाक

न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) में भारत की एंट्री को लेकर पाकिस्तान में घबड़ाहट है। अब पाकिस्तान जी–जान से भारत की एनएसजी में एंट्री रोकने के लिए लॉबिंग में लग गया है। पाक पीएम नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि पाकिस्तान 48 देशों वाले ग्रुप एनएसजी में भारत का प्रवेश रोकने के लिए ग्रुप के लगभग सभी देशों के संपर्क में है। उम्मीद है कि भारत की एंट्री रोकने में पाक का प्रयास सफल साबित होगा।

अमेरिका ने भारत की न्यूक्लियर सप्लायर (एनएसजी) ग्रुप में एंट्री के समर्थन का वादा किया है। अमेरिका के बाद स्विटजरलैंड और जापान ने भी भारत का सपोर्ट किया जा रहा है। अगर भारत को एंट्री मिलती है तो वह न्यूक्लियर कॉमर्स को आगे बढ़ा सकेगा। चीन भारत की जगह पाक को ग्रुप में एंट्री दिलाना चाहता है। अगर भारत को ग्रुप में एंट्री मिल जाती है तो उसके पास आगे वीटो अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में वह पाक की इस ग्रुप में एंट्री को रोक सकता है। पाकिस्तान में इसी बात को लेकर और बेचौनी है।

अमेजन का भारत में 20 हजार करोड़ का निवेश

अमेरिकी ई–कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में और तीन अरब डॉलर (करीब 20,000 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी। यूएस–इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआइबीएस) की सालाना बैठक में कंपनी के संस्थापक एवं सीईओ जेफ बेजोस ने यह एलान किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। निवेश की यह राशि पूर्व में घोषित दो अरब डॉलर (लगभग 13,400 करोड रुपये) के अलावा होगी। कंपनी तेज रफ्तार भारतीय अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते रुझान का पूरा लाभ उठाना चाहती है। यूएसआइबीएस से जुड़ी सभी कंपनियां कुल मिलाकर 45 अरब डॉलर (तकरीबन 3,00,000 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त निवेश करेंगी। इस मौके पर बेजोस ने कहा कि अमेजन

पहले ही भारत में 45,000 लोगों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा कर चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को देखते हुए कंपनी आगे भी ऐसा करती रहेगी। अमेजन ने वर्ष 2013 के दौरान भारतीय बाजार में प्रवेश किया था। अमेजन अमेरिकी कंपनी को फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी घरेलू ई–कॉमर्स दिग्गजों से तगड़ी टक्कर मिल रही है।

'ट्रांसफोर्मिंग इंडिया' नया एक्शन प्लान

मोदी सरकार देश में रोजगार बढ़ाने और बेहतर ई–गवर्नेंस के लिए नया प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत नीति आयोग ने ट्रांसफार्मिंग इंडिया का एक्शन प्लान बनाया है। जो कि 35 से ज्यादा सेक्टर पर फोकस करेगा। इन सभी सेक्टर में मोटे तौर पर 7 एजेंडे के

आधार पर तय समय में एक्शन लिए जाएंगे। नीति आयोग के इस एक्शन प्लान पर एक सीरिज शुरू कर रहा है। जिसमें प्रमुख सेक्टर के एजेंडे और प्लान का ब्यौरा दिया जाएगा।

इसके तहत कृषि और किसान कल्याण, एग्रीकल्चर रिसर्च, आयुष, फॉर्मास्युटिकल्स, सिविल एविशन, एसएमई सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, डिसइनवेस्टमेंट स्ट्रैटजी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, टेलिकम्युनिकेशंस, हैवी इंडस्ट्रीज जैसे 35 से ज्यादा सेक्टर को लिया गया है।

यह प्लान 7 एजेंडे पर बना है जिनमें– 1. गुड गवर्नेंस, 2. नए रोजगार पैदा करने की स्ट्रैटजी, 3. किसानों की आय बढ़ाने का प्लान, 4. सभी के लिए क्वॉलिटी एजुकेशन और हेल्थ सेवाएं, 5. स्वच्छ भारत और नमामि गंगे अभियान, 6. इन्क्लूसिव और समान ग्रोथ, 7. एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन है।

कर्ज को मोहताज छोटे व मझोले किसान

कृषि गणना 2010–11 के अनुसार देशभर में 13.8 करोड़ कृषि जोत हैं जिसमें से 11.7 करोड़ यानी 85 प्रतिशत जोत छोटे और मझोले क्षेत्र की हैं। देश में 43 प्रतिशत बुआई इन छोटी और मझोली जोत में होती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मार्च 2015 तक की स्थिति के अनुसार बैंकों के कुल समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का मात्र 6 प्रतिशत ही छोटे और मझोले किसानों को दिया गया है। सरकारी संस्था नेशनल सेंपल सर्वे ऑफिस की

एक ताजा रिपोर्ट भी बताती है कि मात्र 43 प्रतिशत किसानों को ही बैंक से ऋण की सुविधा प्राप्त है जबकि 25 प्रतिशत किसान अब भी कर्ज के लिए साहूकारों पर निर्भर हैं। आरबीआइ ने किसानों के लिए प्राथमिक क्षेत्र के तहत 8 प्रतिशत ऋण किसानों को देने का लक्ष्य तय किया था। हालांकि अब तक यह लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है।

शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय

फोर्ब्स की 2016 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में एसबीआई की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अरुंधती भट्टाचार्य और आई.सी.आई. सी.आई. बैंक की प्रबंध निदेशक चंदा कोचर समेत चार भारतीय महिलाएं शामिल हैं। जर्मनी की चांसलर एंजला मर्केल शीर्ष पर हैं और इसमें पेप्सीको प्रमुख इंदिरा नूयी, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ और एचटी मीडिया की प्रमुख शोभना भरतिया शामिल हैं। फोर्ब्स ने कहा कि इस साल की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में विश्व की सबसे तेज–तर्रार, सख्त महिला कारोबारी नेतृत्व, उद्यमी, निवेशक, वैज्ञानिक, परोपकारी महिलाएं और मुख्य कार्यकारी शामिल हैं। 60 वर्षीय भट्टाचार्य इस सूची में 25वें स्थान पर हैं और वह सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को वसूली में अटके 11 अरब डॉलर के भारी–भरकम ऋण का सामना करना पड़ रहा है।

मजूमदार–शॉ इस सूची में 77वें स्थान पर हैं। अपने दम पर सफल उद्यमी बनीं 63 वर्षीय मजूमदार–शॉ ने बायोकॉन को इन्स्यूलिन क्षेत्र की बड़ी कंपनी के तौर पर स्थापित किया। भरतिया 93वें स्थान पर हैं। नूई इस सूची में 14वें स्थान पर हैं। इनके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रैटिक पार्टी की उम्मीदार हिलेरी क्लिंटन दूसरे स्थान पर हैं। अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा (13वें), महारानी एलिजाबेथ–1 (29वें), बांग्लोदश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (36वें), नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी (52वें) और यूनेस्को की महानिदेशक आईरीना बाकोवा (89वें) का स्थान है।

स्मार्ट शहर में होंगे स्मार्ट बैंक

स्मार्ट शहर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरु करने के बाद सरकार अब इन शहरों में स्मार्ट बैंकिंग सुविधा देने की तैयारी भी कर रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे स्मार्ट शहरों के लिए अभी से अपने कामकाज का तरीका स्मार्ट बनाने में जुट जाएं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की उच्च स्तरीय बैठक में मंत्रालय ने यह निर्देश दिया। सरकार

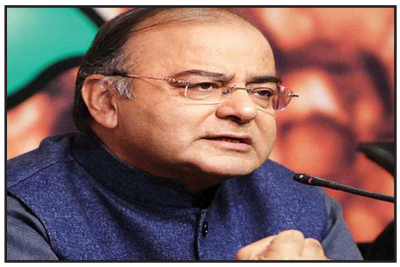

बैंकों के डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहन दे सकती है। वैसे भी अगर डिजिटल लेन–देन बढ़ता है तो बैंकों को लागत भी कम आएगी। बैंकों को प्रौद्योगिकी के बेहतर इस्तेमाल के साथ–साथ सभी एटीएम मशीनों को 'आधार' के लायक बनाने को कहा है। ऐसा होने पर सभी मौजूदा एटीएम मशीनों और नए एटीएम को ऐसा बनाना होगा जो ग्राहक की अंगुलियों की छाप (बॉयोमीट्रिक्स) को पहचान सकें। ऐसा होने पर एटीएम कार्ड की सुरक्षा बढ़ जाएगी और उनसे फ्रॉड की संभावना भी लगभग खत्म हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की घोषणा की है जिसमें से पहले चरण में 20 शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है।

यूरोप के 40 देश कालेधन पर भारत के साथ

ब्लैक मनी और करप्शन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने यूरोप के 40 देशों के ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत इन देशों के साथ टैक्स चोरी की सूचनाओं का आदान–प्रदान आसानी से कर सकेगा।

यूके के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उन देशों की लिस्ट जारी की जिन्होनें इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा कि साइन करने वाले सभी देश टैक्स चोरी और करप्शन को रोकने के लिए आपस में सूचनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। इसके अगली स्टेज में एक ग्लोबल स्टेंण्डर्ड बनाने पर काम किया जाएगा।

यूरोप के बाहर भारत के अलावा जिन देशों ने इस समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए हैं उनमें अफगानिस्तान, नाइजिरिया, मेक्सिको और यूएई शामिल हैं।

यह ग्रुप बनाने का मकसद सदस्य देशों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों और टैक्स अथॉरिटीज के बीच पारदर्शिता से डाटा एक्सचेंज करना है। इस ग्रुप में यूरोप के अधिकतर देशों ने ऑटोमेटिक एक्सचेंज मैकेनिस्म का हिस्सा बनने को हस्ताक्षर किए लेकिन, स्विजरलैंड इसका हिस्सा बनने को राजी नहीं हुआ।

गन्ना किसानों का 6225 करोड़ रू. बकाया

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सत्र 2015–16 के कुल बकाये राशि में से 87 प्रतिशत का अब तक भुगतान कर दिया गया है फिर भी किसानों का मिलों पर अब भी 6225 करोड़ रुपये बकाया है। वर्ष 2015–16 के दौरान उत्तर प्रदेश में 2428 करोड़, कर्नाटक में 1325 करोड़, महाराष्ट्र में 883 करोड़, तमिलनाडु में 610 करोड़, गुजरात में 255 करोड़, उत्तराखंड में 198 करोड़, आन्ध्र प्रदेश में 181 करोड़, बिहार में 143 करोड़, तेलंगना में 99 करोड़, ओडिशा में 32 करोड़, पंजाब में 28 करोड़, मध्य प्रदेश में 16 करोड़, छत्तीसगढ में 15 करोड़, पुड्डुचेरी में 11 करोड़ और गोवा में 1 करोड़ रुपये बकाया हैं।

सरकार ने खरीदीं 1.11 लाख टन दालें

बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार किसानों से अब तक 1.11 लाख टन दालें खरीद चुकी है। उसने 38,500 टन दालों का आयात करने के लिए अनुबंध भी किया है। अनुबंधित दालों में से करीब 13 हजार टन पहले ही देश में आ चुकी हैं। छह हजार टन आनी हैं। खुदरा मूल्यों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत सरकार ने ये कदम उठाए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों से बफर स्टॉक से दालों के आवंटन के लिए अपनी मांग रखने को भी कहा है। साथ ही इन्हें उचित मूल्यों पर बेचने के निर्देश दिए हैं। ये दालें राज्यों की ओर से 120 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की दर से नहीं बेची जाएंगी। सरकार ने बीते साल दिसंबर में डेढ़ लाख टन दालों की खरीद करके इसका बफर स्टॉक तैयार करने का फैसला किया था। खुदरा बाजार में कीमतों के चढ़ने पर इसका उपयोग किया जाना है।

आरकॉम शुरू करेगा 4G सर्विसेज

रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) देशभर में कई चरणों में अपने दम पर 4G सर्विसेज लांच करने की तैयारी में है। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे प्रमुख सर्कल्स में मध्य अगस्त से इसकी शुरुआत होगी और यह क्लीयरेंस मिलने

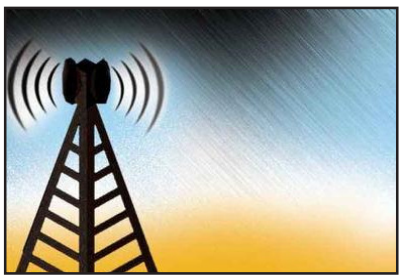

के साथ ही धीरे–धीरे रिलायंस जियो इंफोकॉम के साथ अपने शेयरिंग एग्रीमेंट का फायदा उठाएगा।

कैंसर–डायबिटीज सहित 56 दवाइयां होंगी सस्ती

नेशनल फर्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने कैंसर और डायबिटीज सहित 56 दवाइयों के मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय कर दिया है। एनपीपीए की नई कीमत सीमा से जिन कंपनियों की दवाइयों की कीमतों में कमी आएगी उनमें एबॉट हेल्थकेयर, सिप्ला, ल्यूपिन, एलेम्बिक, एलकेम लैबोरेटरीज, नोवार्तिस, बायोकॉन, इंटास

फार्मास्युटिकल्स, हेतेरो हेल्थकेयर और सन फर्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज शामिल हैं। दवाइयों के रेट में 10 से 50 फीसदी तक की कमी की गई है।

एनपीपीए ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि अगर कोई कंपनी दवा के रेट में कमी नहीं करती है और बढ़े प्राइस पर ही बेचती है तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। कंपनी को पूरा बढ़ा हुआ प्राइस और उस पर इंटरेस्ट फाइन के रूप में जमा करना होगा। कंपनियों को इन दवाइयों की कीमतों में एक साल बाद केवल 10 फीसदी प्राइस बढ़ाने की अनुमति मिलेगी।

इंटरनेट 100रू./साल

सबसे सस्ते टैबलेट का सपना लेकर भारतीयों तक पहुंची डाटाविंड अब सबसे सस्ता इंटरनेट का सपना दिखा रही है। कंपनी के अनुसार वह वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (VNO) के लिए

आवेदन करेगी और लाइसेंस मिलने पर मात्र 100 रु. में एक साल तक इंटरनेट सेवा देगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इंटरनेट के लिए सलाना कम से कम 1200 रुपये खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके मद्देनजर उनकी कंपनी मात्र 100 रुपये वार्षिक शुल्क पर आम लोगों को इंटरनेट देना चाहती है। इसके तहत ग्राहक हर तरह से इंटरनेट का उपयोग कर सकेगा।

सरकारी बैंकों को झटका

फंसे कर्ज (एनपीए) की बीमारी व बढ़ते घाटे और बदहाल ग्राहक सेवा के लिए बदनाम सरकारी बैंकों को अब एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय बैंकिंग के इतिहास में पहली बार निजी बैंकों ने नए कर्ज के मामले में सरकारी बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। निजी बैंकों की नए कर्ज की राशि सरकारी बैंकों के मुकाबले डेढ़ गुना ज्यादा तेजी से बढ़ी है। फंसे कर्ज की वजह से ही पिछले वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये घाटा हुआ है।

भारत में पांच गुना बढ़ेगी मोबाइल डाटा खपत

दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन ने एक अध्ययन में

निष्कर्ष निकाला है कि भारत में प्रति स्मार्टफोन औसत मोबाइल डाटा खपत 2021 तक पांच गुना बढ़ेगी और मोबाइल फोनों के कुल ट्रेफिक में इसका हिस्सा 99 प्रतिशत होगा। इसके अनुसार, प्रति स्मार्टफोन (सक्रिय) डाटा खपत 2021 तक पांच गुना बढकर सात जीबी होने की उम्मीद है जो कि 2015 में 1.4 जीबी प्रति माह थी।

विकासशील देश का तमगा हटा भारत से

भारत से विकासशील देश का तमगा हट गया है। विश्व बैंक की विश्लेषण संबंधी सभी रिपोर्टो में उसे 'निम्न मध्य आय' वाले देशों की श्रेणी में रखा जाएगा। उसने अपनी खास रिपोर्टो के लिए देशों के वर्गीकरण के तरीके में फेरबदल किया है। देशों का समूहीकरण बेहतर तरीके से हो, इस मकसद से ऐसा किया गया है। विश्लेषण संबंधी उद्देश्यों के लिए भारत का वर्गीकरण निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर होगा। यह साफ करना जरूरी है कि 'विकासशील देश' या 'विकासशील दुनिया' जैसे शब्दों को सामान्य कार्य में बदला नहीं जा रहा है। यानी इनका भी इस्तेमाल होगा। लेकिन जब बात विशेष

आंकड़ों की होगी तो देशों का सटीक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल नए क्लासिफिकेशन में ब्रिक्स देशों में से बाकी अन्य भारत से बेहतर श्रेणी में पहुंच गए हैं। ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका को उच्च मध्य आय वाली श्रेणी में रखा गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत की श्रेणी में हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था में हैं।

पाकिस्तान पर मेहरबान चीन

पाकिस्तान के रेल नेटवर्क को अधिक बेहतर बनाने और पाकिस्तान–ईरान के बीच एक गैस पाइपलाइन का निर्माण करने के लिए चीन, 8.5 बिलयन अमेरिकी डॉलर (लगभग 57 अरब रुपए) का निवेश करने जा रहा है। पाकिस्तान की बड़ी परियोजनाओं को अधिकृत करने वाली सेंट्रल डिवेलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 10 बिलयन अमेरिकी डॉलर की लागत वाले दो प्रॉजेक्ट्स अप्रूव किए है। इन दोनों ही प्रॉजेक्ट्स के लिए चीन 85 प्रतिशत (8.5 बिलयन अमेरिकी डॉलर) का कर्ज दे रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे को अपग्रेड करने में कुल 8.2 बिलयन अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी जिसमें से 7 बिलयन अमेरिकी डॉलर चीन द्वारा कन्सेशनरी लोन के रूप में दिया जा रहा है। यह प्रॉजेक्ट 46 बिलयन अमेरिकी डॉलर वाले चीन–पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पैकेज का एक हिस्सा है। इस अग्रीमेंट पर चीन के राष्ट्रपति ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान अप्रैल 2015 में हस्ताक्षर किए थे। ❑❑

पर्यावरण जागरूक रैली

4 जून, 2016 को पर्यावरण जागरूकता रैली साकची गोल चक्कर (बिष्टुपुर) से मोदी पार्क (कीनन स्टेडियम) तक निकाली गई। रैली को पोटका विधानसभा के विधायक श्रीमती मेनका सरदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पर्यावरण संरक्षण संबंधी नारे जैसे– 'पेड़ लगावें डगर–डगर, प्रदूषण बचायें शहर–शहर'', ''एक–एक बूंद बचायेंग–बच्चों का भविष्य बनायेंगे'' आदि लगाये जा रहे थे। रैली मोदी पार्क में पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। सभा को संबोधित करते हुए मेनका सरदार ने कहा कि आज पर्यावरण वैश्विक समस्या बन गया है। जल स्तर जिस तरह से कम हो रहा वह पूरे विश्व के लिये चिंतन का विषय है। अगर लोग अभी भी सजग नहीं हुए, तो जो परिस्थिति होगी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जब लोग केवल अपने बारे में सोचने में व्यस्त हैं ऐसे समय में पर्यावरण के लिये चिंतन करने के लिये आए स्वदेशी जागरण मंच इस अभियान ''पर्यावरण पहल'' के लिए बधाई योग्य है।

उपस्थित सभी लोगों को संकल्प दिलवाया गया कि– 1. जल को प्रदूषित या बर्बाद नहीं करेंगे, 2, यथासंभव जल संरक्षण करेंगे, 3. अपने जीवनकाल में कम से कम 10 वृक्ष लगायेंगे, 4.प्राकृतिक संसाधनों का दुरूपयोग नहीं करेंगे।

इस अवसर पर मनोज कुमार सिंह, बंदेशंकर सिंह, नंदजी प्रसाद, बिमल जालान, अशोक गोयल, अनिल राय, जे.के.एम. राजू, राजकुमार साह, सी.पी. सिंह, अमित मिश्रा, गौरवशंकर, कौशल किशोर, राकेश पांडे, अभिषेक बजाज, विजय सिंह, अमर कुमार सिंह, सुखदेव सिंह, रतन महतो, प्रकाश सिंह, राजेश सिंह, पी.के. दत्ता, शंभू दूबे, सुरेश शर्मा, संतोष राय, पूर्णिमा, ममता सिंह, प्रीति सिन्हा, विनिता सहाय, सुनीता सिंह, मंजू ठाकुर, जयंत श्रीवास्तव, लाला शर्मा, देव कुमार, मुकेश कुमार, राजेश शर्मा, राघवेन्द्र सिंह, रोशन सिंह, पंकज सिंह, सुदेश्वर सिंह, सीमा जयसवाल, अजय कुमार, दिलीप कुमार प्रेम सहित सहयोगी सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ❑

उद्योगों में विदेशी निवेश वापस लिया जाए: कमलजीत

स्वदेशी जागरण मंच करनाल इकाई की मासिक गोष्ठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में हुई। अध्यक्षता हरियाणा व दिल्ली संगठक श्री कमलजीत ने की। स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद बैठक (भोपाल–म.प्र.) की जानकारी देते हुए कमलजीत ने कहा कि ई–कॉमर्स और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों एवं खाद्य विपणन में विदेशी निवेश वापस लिया जाए, क्योंकि ई–कॉमर्स की वेबसाइटें अपनी हिंसक कीमत नीति के माध्यम से स्वदेशी ई–कॉमर्स कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच अपने गठन काल 1991 से की देशहित व समाजहित के मुद्दे पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता से उठाता रहा है। उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि स्वदेशी का विचार घर–घर तक पहुंच सके। बैठक में जैविक खेती व जी.एम. फसलों से संबंधित विषय की जिम्मेदारी डॉ. अशोक शरयाल व प्रकाश पाटिल, मधुमक्खी पालन व कृषि रसायन विषय की जिम्मेदारी डॉ. ओ.पी. चौधरी, देशी गाय पर कार्ययोजना की जिम्मेदारी रविन्द्र व बौद्विक संपदा अधिकार तथा नागरिक विषय की जिम्मेदारी दुलीचंद रमन को दी गई। इस कार्यक्रम में कमलजीत, डॉ. अशोक शरयाल, श्री प्रकाश पाटिल, डॉ. ओ. पी. चौधरी, श्री रविन्द्र, श्री दुलीचंद, रामपाल, संदीप खोखर, प्रकाश पाटिल व विक्की मंहत आदि ने भागीदारी की। ❑❑